www.deshbandhu.co.in खबरें लगातार ...

पत्र नहीं; मित्र

संपर्क : deshbandhubpl1@gmail.com

देशबन्धु

वर्ष – 37 । अंक –249 । भोपाल, गुरुवार 10 सितम्बर 2026 । पृष्ठ–8 । मूल्य – 2.00 रुपए

तमिलनाडु से तेलंगाना तक बढ़ेगी रेलवे की पहुंच पृष्ठ 2

सिमोन द बुवा के देश में नारी उत्पीड़न
असलियत से ज़्यादा गणितीय हो सकती है भारत की तेज़ विकास दर पृष्ठ 4

नरोदा में किराये के कमरों में लग रही कक्षाएं, उकायला स्कूल का प्लास्टर गिरा, फर्श उखड़ा पृष्ठ 6

दुबई के निवेशकों को भाया मध्य प्रदेश : 53 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पृष्ठ 8

सार-समाचार

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विवि के नए कुलपति होंगे बिमलेन्द्र कुमार

भोपाल, देशबन्धु। राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष मंगुभाई पटेल ने पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बिमलेन्द्र कुमार को सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रोफेसर बिमलेन्द्र कुमार को कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए कुलपति नियुक्त किया है।

पुणे में पेपर लीक विवाद के बीच छात्र ने की आत्महत्या

पुणे, एजेंसी। पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पेपर लीक की बार-बार हो रही घटनाओं और आर्थिक तंगी के कारण उसने यह कदम उठाया। मृतक की पहचान प्रथमेश देशमुख के तौर पर हुई है। पुलिस को शक है कि गंभीर आर्थिक परेशानियों, जिसमें 2.5 लाख रुपए का बकाया कर्ज भी शामिल है, के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया। इस दुखद घटना ने राज्य में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।

भारत ने नेपाल को भेजी 35 टन राहत और बचाव सामग्री

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय वायुसेना का आठवां विमान बुधवार को 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर नई दिल्ली से काठमांडू भेजा गया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने इसकी जानकारी दी। नेपाल 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने की कोशिश कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अभी भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक्स पर कहा, 'भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। एनडीआरएफ के उपकरण, बचाव का सामान, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी चीजों समेत 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर आईएएफ का आठवां विमान काठमांडू के लिए रवाना हो गया।'

मनोज जरांगे बोले- 'सरकार को घुटनों पर लाएंगे'

मुंबई, एजेंसी। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि मराठा समाज मुंबई आने के लिए तैयार है। हम सरकार को घुटनों पर लाएंगे। मराठा समाज पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही, मनोज जरांगे ने मराठा समाज से अपील करते हुए कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन कोई भी आत्महत्या न करे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत मनोज जरांगे ने कहा कि अगर मराठा समाज के लोग आत्महत्या करते हैं, तो सरकार को उसका कोई दुख नहीं है। सरकार ने मराठों की जान ली है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा।

हंदवाड़ा में हाइब्रिड पूर्व-आतंकवादी पकड़ा गया

जम्मू, एजेंसी। पुलिस ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में हाइब्रिड मोड में काम कर रहे एक पूर्व-आतंकवादी द्वारा चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एक बयान में पुलिस ने कहा कि हंदवाड़ा पुलिस को एक पूर्व-आतंकवादी की गतिविधियों के बारे में पक्की जानकारी मिली थी। यह व्यक्ति प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के एक मॉड्यूल के हिस्से के तौर पर हंदवाड़ा-कुपवाड़ा इलाके में हाइब्रिड आतंकवादी के रूप में काम कर रहा था। तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 21 आरआर और केरिपुब की 22वीं बटालियन के साथ मिलकर हंदवाड़ा शहर में चिन्हित जगह पर एक संयुक्त अभियान चलाया और गहन सुरक्षा जांच के बाद आरोपी को पकड़ लिया।

बंगाल का दौरा करेंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

कोलकाता, एजेंसी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अगले सप्ताह दो दिवसीय दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं, जहां उनका आयोजन कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि उनके 15 सितम्बर को राज्य में आने का कार्यक्रम है। वे राज्य पार्टी नेतृत्व के साथ कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। उनके साथ पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष भी होंगे। इन बैठकों में नई राज्य समिति के गठन से लेकर संगठन में जरूरी फेरबदल तक कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

जहरीली शराब से मौतों के मामले में दोषी बचें नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्ती के निर्देश

जिम्मेदारों पर हो कठोर कार्रवाई : मुख्यमंत्री

सागर, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए और नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेदारी तय कर पूरी गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को बुंदेलखंड मेडिकल महाविद्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और असामाजिक गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। जिले के साथ आसपास और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गहन जांच अभियान चलाया जाए। जहां भी संदिग्ध गतिविधियों की आशंका हो, तत्काल पड़ताल कर कठोर कार्रवाई की जाए।

डॉ. यादव ने अवैध जहरीली शराब की सामग्री जब्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री दोबारा लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई में निष्पक्षता और विवेकशीलता का पूरा ध्यान रखा जाए। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया जाए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और अन्य

माध्यमों से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जाए। नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को साथ लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

कठोर कानून का प्रावधान : मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब के मामलों में कठोर कानून का प्रावधान है। संबंधित धाराओं के तहत हत्या से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कठोर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध अतिक्रमण अथवा अवैध गतिविधियों के जरिए अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाकर अवैध शराब की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के प्रयास होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने शराब से प्रभावित और बीमार लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने इस घटना में अपने एक से अधिक सदस्यों को खोया है, उनका दुख अत्यंत पीड़ादायक है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शासन के साथ समाज को भी मिलकर प्रयास करना होगा। पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, वीरेंद्र सिंह लोधी, निर्मला सप्रे, ब्रज बिहारी पटेरिया सहित जनप्रतिनिधि, संभागायुक्त दिलीप कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक एसएस चौहान, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया तथा चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे।

शराब कांड की होगी न्यायिक जांच

सागर/भोपाल, देशबन्धु। सागर में अवैध शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के साथ तथ्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो सके। डॉ. यादव के निर्देश पर दिलीप कुमार ने सागर संभाग के आयुक्त के रूप में कमान संभाल ली है। वहीं, इरशाद वली को सागर संभाग की पुलिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए आईजी बनाया गया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से सरकार की सख्त प्रशासनिक कार्यशैली और जवाबदेही तय करने की नीति स्पष्ट होती है। गौरतलब है कि डॉ. यादव का कहना है कि गंभीर मामलों में लापरवाही अथवा अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिलीप कुमार ने संभागायुक्त की कमान संभाली, इरशाद को आईजी का जिम्मा

छात्र को नोटिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

- सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जारी नोटिस पर सवाल उठाए
- अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेगे

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के प्रस्तावित छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कथित तौर पर प्रचार कर रहे एक छात्र को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि जब विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर पहले ही रद्द की जा चुकी थीं और यह निर्देश दिया गया था कि सीजेपी विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए, तो ऐसा नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने उठाया। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दूसरे वर्ष के एक छात्र को नोटिस जारी कर शांति बनाए रखने के लिए पांच लाख रुपए का निजी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया था। बताया जाता है कि बाद में यह नोटिस वापस ले लिया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल किया कि विरोध प्रदर्शन से जुड़े छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के उच्चतम न्यायालय के पहले के निर्देश के बावजूद मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी उप्र सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। छात्रा व एक्टिविस्ट आकृति चौधरी की एनएसए हिरासत रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जाएगी। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की एनएसए के तहत हिरासत को रद्द कर दिया था और 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मुआवजा उनकी हिरासत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाए। इसमें गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और अन्य अधिकारी शामिल हैं।

राहुल ने सड़कों के गड्ढ़ो पर अफसरों को घेरा

तस्वीरें दिखाकर पूछा, क्यों नहीं हुई कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिशा समिति की बैठक में रायबरेली की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बैठक के दौरान अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया और सड़क मरम्मत का काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। दिशा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा और सड़कों के रखरखाव को लेकर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने अधिकारियों से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा, ताकि सड़कों की स्थिति और मरम्मत कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

जूडा का आंदोलन खत्म, स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत होगी वृद्धि

भोपाल, देशबन्धु। मांगों को लेकर तीन दिन से जारी जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिकित्सा छात्रों के स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गांधी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि छात्रों की इस मांग पर पहले से ही चर्चा चल रही थी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस विषय पर सतत संवाद कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त हुए आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और काम पर लौट आए। आंदोलन के चलते बुधवार को भी हमीदिया अस्पताल में बाह्य रोगी सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि आपात सेवाएं जारी रहीं। उप मुख्यमंत्री ने युवा चिकित्सकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा भाव और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

(संबंधित समाचार पृष्ठ 3 एवं 8 पर)

महानगरों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्यों को पत्र लिखेगा गृह मंत्रालय

पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों के समाधान की कवायद

• जोगेंद्र सोलंकी

नई दिल्ली, देशबन्धु। गृह मंत्रालय सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को पत्र लिखने की तैयारी में है, जिसमें उनसे पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए महानगरों में समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया जाएगा। यह फैसला पूर्वोत्तर के लोगों से जुड़े मुद्दों पर मंत्रालय की निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। इससे दो दिन पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में मणिपुर के 54 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह पर क्रूर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस कदम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों, जो इस इलाके से बाहर रहते हैं, खासकर बड़े शहरी इलाकों में, उनके साथ होने वाले भेदभाव, परेशानी और दूसरी शिकायतों को दूर करने के मौजूदा सिस्टम को मजबूत करना है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के पूर्वोत्तर डिवीजन के संयुक्त सचिव नीरज कुमार बंसोड़ ने की और इसमें दिल्ली पुलिस, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और गृह मंत्रालय के अधिकारियों समेत अलग-अलग राज्यों और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में शामिल समिति के दूसरे सदस्यों में डॉ. अलाना गोलमेई, सचिव, पूर्वोत्तर समर्थन केंद्र, नई दिल्ली, डॉ. मिजुम न्योडू, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जोरम मैवियो, मॉनिटरिंग कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल थे। जोरम मैवियो ने खास बातचीत में बताया कि गृह मंत्रालय शुरू में उन मेट्रो शहरों पर ध्यान देगा जहां पूर्वोत्तर के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। मैवियो ने कहा, 'यह पत्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लिखा जाएगा।' दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई महानगरीय शहरों में पहले से ही पूर्वोत्तर के लिए नोडल ऑफिसर हैं। हालांकि, मॉनिटरिंग कमिटी के सदस्यों को लगा कि मौजूदा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने और बेहतर तालमेल बिठाने की जरूरत है। समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और उसे मजबूत करने की जरूरत पर चर्चा करने के अलावा, प्रस्तावित उत्तर पूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान की प्रगति की भी समीक्षा की। बता दें कि गृह मंत्रालय की निगरानी समिति का गठन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव से संबंधित मुद्दों और शिकायतों की निगरानी करना और उनका समाधान करना है।

- मणिपुरी संगीतकार की हत्या के बाद जागी सरकार
- मौजूदा व्यवस्थाओं में बेहतर तालमेल की जरूरत

बीज माफियाओं के खिलाफ 'सीड एक्ट' लाने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के अन्नदाताओं को नकली और घटिया बीजों के नुकसान से हमेशा के लिए सुरक्षित करने की दिशा में मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और आत्मनिर्भर किसान के विजन को अमलीजामा पहनाते हुए केंद्र सरकार एक नया और सख्त 'सीड एक्ट' लाने की तैयारी में है। इस कानून को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को देशभर के प्रमुख किसान संगठनों के शीर्ष नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीड कानून के मसौदे पर सीधे किसानों के जमीनी अनुभव, सुझाव और पक्ष को शामिल करना है ताकि बीज माफियाओं के खिलाफ एक अचूक और प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जा सके। प्रस्तावित नए 'सीड एक्ट' के तहत नकली, मिलावटी या घटिया बीज बेचने वाली कंपनियों और कारोबारियों के खिलाफ भारी जुर्माने और जेल की सजा जैसे बेहद सख्त कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं। कई बार खराब बीज के कारण किसान की महीनों की गाढ़ी कमाई और खून-पसीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि कानून ऐसा बने जो बीज की गुणवत्ता और पारदर्शी ट्रेसिंग सिस्टम की शत-प्रतिशत गारंटी दे, साथ ही किसानों के पारंपरिक बीजों के अधिकारों की भी रक्षा करे।

देशभर के किसान नेताओं संग संवाद करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

भाजपा को कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा चंदा मिला

नई दिल्ली, एजेंसी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस की चुनावी कमाई में बड़ा अंतर सामने आया है। चुनाव आयोग के सामने दाखिल खर्च और आय से जुड़े ब्योरे के मुताबिक, भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय को इस अवधि में करीब 1,472.8 करोड़ रुपए मिले। यह कांग्रेस की पांचों राज्यों और केंद्रीय इकाइयों की कुल शुद्ध प्राप्तियों 207.17 करोड़ रुपए से सात गुना से भी ज्यादा है। भाजपा का उपलब्ध आंकड़ा केवल केंद्रीय मुख्यालय का है।

15 मार्च से 6 मई तक असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्रीय मुख्यालय और पांचों राज्यों की इकाइयों को मिलाकर 207.17 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां बताईं। उसका कुल चुनावी खर्च 248.55 करोड़ रुपये रहा। दूसरी ओर, भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय को इसी अवधि में 1,472.8 करोड़ रुपए मिले। भाजपा के केरल और पश्चिम बंगाल चुनावों के खर्च से जुड़े ब्योरे अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसलिए भाजपा की कुल प्राप्तियां उपलब्ध आंकड़े से भी अधिक हो सकती हैं। भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय की वित्तीय स्थिति में चुनाव अवधि के दौरान बढ़ोतरी हुई। 15 मार्च को उसके पास करीब 6,722.6 करोड़ रुपए का समापन शेष था। 6 मई तक यह बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपए हो गया। यानी चुनाव अवधि में केंद्रीय मुख्यालय के पास मौजूद रकम में करीब 904.6 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई।

- 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को मिला 1,473 करोड़ चंदा
- भाजपा के पास 7,627.2 करोड़ रुपए

कांग्रेस ने कागजी पार्टियों के चंदा मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की

चंदे के नाम पर 10 हजार करोड़ की हेराफेरी

- भाजपा ने कई को अपनी सी टीम के रूप में खड़ा किया
- देशभर में ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या करीब 3260

नई दिल्ली, देशबन्धु। कागजी पार्टियों के जरिए 10 हजार करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने देशभर में बहुत सारे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सी टीम के रूप में खड़ा किया है।

बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कुछ दिनों पहले एक मीडिया संस्थान द्वारा प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए कहा कि यह देश का सबसे बड़ा टैक्स घोटाला है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें गंभीर अनियमितता नजर आ रही है, लेकिन सरकार अपने चहेतों को बचाने के लिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में एडीआर की रिपोर्ट आई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। झारखंड के कुछ आयकर अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े को आपराधिक मामला बताते हुए मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोहिल आरोप लगाया कि भाजपा ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त कई दलों को अपनी सी टीम के रूप में खड़ा किया है, जिनके जरिए टैक्स की चोरी और काले धन को सफेद बनाने का काम किया जा रहा है। देशभर में ऐसे दलों की संख्या करीब 3260 है। इन फर्जी दलों को चंदा देकर टैक्स चोरी करने वाले बोगस डोनर्स पर आयकर

कानून के तहत 200 फीसदी जुर्माना और आपराधिक मामले दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इस फर्जीवाड़े में शामिल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स व फर्जी दलों के कर्ता धर्ताओं और चंदा देने वाली कंपनियों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही यह भी बताया जाए कि इन फर्जी दलों के चलाने वाले कितने लोग अब भाजपा में हैं? गोहिल का कहना था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे पर टैक्स की छूट का प्रावधान है। इसी का दुरुपयोग कर इन फर्जी दलों को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया गया। इसके बदले इन फर्जी दलों के लोगों ने दो से 15 फीसदी कमीशन काटकर शेष राशि चंदा देने वालों को लौटा दी। आयकर विभाग और ट्रिब्यूनल ने भी इस फर्जीवाड़े को स्वीकार किया है।

काले धन को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे राजनीतिक दलों को मिले चंदे और उनके खर्च का पूरा ब्योरा अपनी वेबसाइट पर जारी करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। काले धन को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इस मामले पर अभी तक खामोशी क्यों है? इस मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए ताकि पूरा सच सामने आ सके।

सार-समाचार

भागवत कथा में गोवर्धन पूजा प्रसंग सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु

शिवपुरी, देशबन्धु। श्री राधे कृष्ण सेवा समिति के तत्वावधान में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित मुकुंद विनोद गार्डन में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा व्यास आचार्य विक्रम महाराज ने श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं और गोवर्धन पूजा के प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। आचार्य विक्रम जी महाराज ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के अहंकार से मुक्त कराकर गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बताया। जब इंद्र देव ने क्रोधित होकर ब्रज में मूसलाधार वर्षा की, तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। कथा के दौरान गोवर्धन लीला का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे। कथा स्थल पर भक्तों ने भजन-कीर्तन के साथ भगवान श्रीकृष्ण और गिरिराज महाराज का स्मरण किया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया।

महाराज दक्ष की जयंती पर प्रजापति समाज ने निकाला चल समारोह

शिवपुरी, देशबन्धु। महाराज दक्ष की जयंती पर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी चल समारोह निकाला गया। इस चल समारोह में कोलारस नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रजापति समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री शामिल हुए। इनका दक्ष प्रजापति समाज सेवा युवा समिति कोलारस के दीपक प्रजापति द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। चल समारोह में दक्ष प्रजापति समाज सेवा युवा समिति कोलारस के रामदयाल प्रजापति, सीताराम प्रजापति, रानू प्रजापति, शिक्षक महेश प्रजापति, दाताराम प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, दीपक प्रजापति, देवेंद्र प्रजापति, धर्मेंद्र प्रजापति, अभिषेक प्रजापति आदि सहित समस्त प्रजापति समाज के लोग शामिल हुए।

झारखंड में मतदाता सूची को लेकर अहम निर्देश

रांची, एजेंसियां। झारखंड में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों को ऐसे युवाओं की पहचान कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), दावा-आपत्ति की सुनवाई, नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सेवाओं की समीक्षा की। के. रवि कुमार ने खास तौर पर उन मतदान केंद्रों की समीक्षा करने को कहा, जहां नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए शून्य या केवल एक से पांच फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से पात्र युवाओं की पहचान की जाए। जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष हो रही है और वे मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उनसे फॉर्म-6 और जरूरी घोषणा-पत्र लेकर उनका पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

कैबिनेट ने 10,021 करोड़ रुपए की 5 मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

तमिलनाडु से तेलंगाना तक बढ़ेगी रेलवे की पहुंच

रेलवे नेटवर्क में 540 किमी की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को भारतीय रेलवे की पांच महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। लगभग 10,021 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, माल ढुलाई को तेज करना और दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में रेल संपर्क को मजबूत बनाना है। इन परियोजनाओं को वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंजूर की गई परियोजनाओं में अरक्कोनम-रेनिगुंटा तीसरी और चौथी लाइन (77 किमी), व्हाइटफील्ड-बंगारपेट तीसरी और चौथी लाइन (47 किमी), होसुर-ओमालुर दोहरीकरण (147 किमी), सेलम-करूर-दिंडीगुल दोहरीकरण (159 किमी) और सिकंदराबाद (घाटकेसर)-काजीपेट मल्टीट्रैकिंग (110 किमी) शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी।

52 लाख लोगों को होगा फायदा: ये

परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के कुल 17 जिलों को कवर करेंगी। सरकार के अनुसार, इन रेल परियोजनाओं से लगभग 2,121 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जहां करीब 52 लाख लोगों की आबादी निवास करती है। रेल मंत्रालय का कहना है कि बढ़ी हुई लाइन क्षमता से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम होगी, परिचालन दक्षता में सुधार आएगा और रेल सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही, इन मार्गों पर वर्तमान में मौजूद जाम और परिचालन बाधाओं को भी कम करने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं की योजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को अधिक कुशल बनाना है।

कई प्रमुख धार्मिक, पर्यटन स्थलों को मिलेगा लाभ: रेल नेटवर्क विस्तार का लाभ कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी मिलेगा, जिनमें तिरुपति, तिरुत्तानी स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर, तिरुचानूर का श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर, कोटिलिंगेश्वर मंदिर, बंगारू तिरुपति, कोलार गोल्ड फील्ड्स, होगेनक्कल जलप्रपात, होसुर किला, मेट्टूर बांध, कोडाइकनाल हिल्स, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, नमक्कल अंजनेयर मंदिर, यदागिरिगुट्टा मंदिर, भोंगिर किला, सुरेंद्रपुरी और स्वर्णगिरि मंदिर जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। सरकार का मानना है कि बेहतर रेल संपर्क से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इन प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

-अरक्कोनम- रेनीगुंटा तीसरी और चौथी लाइन - 77 किलोमीटर

-व्हाइटफील्ड- बेंगलुरु तीसरी और चौथी लाइन - 47 किलोमीटर

-होसुर- ओमलूर दोहरीकरण - 147 किलोमीटर

-सलेम- करूर - डिंडीगुल दोहरीकरण - 159 किलोमीटर

-सिकंदराबाद (घाटकेसर)- काजीपेट मल्टी-ट्रैकिंग - 110 किलोमीटर

एमपी गेम उड़ान की होगी शुरुआत

मध्य प्रदेश में गेम डेवलपमेंट की नई प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 24 से 3 दिवसीय गेम जैम

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में उभरती गेम डेवलपमेंट प्रतिभाओं की पहचान करने और प्रोत्साहित कर उद्योग से जोड़ने के उद्देश्य से 'एमपी गेम उड़ान ङ्क मध्यप्रदेश गेम जैम' का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें भागीदारी नि:शुल्क है। विद्यार्थियों और पहली बार गेम डेवलपमेंट में भाग लेने वाले डेवलपर्स को विशेष रूप से आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतिभागी इंडी कनेक्ट पर उपलब्ध 'एमपी गेम उड़ान' पेज के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं।

भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 'एमपी गेम उड़ान' का आयोजन 24 से 26 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों, गेम डेवलपर बनने के इच्छुक युवाओं, प्रोग्रामर्स, कलाकारों, डिजाइनर्स और स्टोरीटेलर्स को एक मंच मिलेगा। प्रदेश के क्रिएटर्स के लिए ऑनलाइन भागीदारी का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। गेम जैम को केवल तीन दिवसीय प्रतियोगिता के रूप में नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश में जमीनी स्तर पर मजबूत गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में तैयार किया गया है। इसके माध्यम से प्रतिभाओं, उद्योग विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय डेवलपर समुदाय को एक साथ लाया जाएगा।प्रतिभागियों को गेम जैम की शुरुआत में, घोषित की जाने वाली थीम पर एक मौलिक और खेलने योग्य गेम तैयार करने की चुनौती दी जाएगी। गेम के विकास की पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें उद्योग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, लर्निंग सेशंस और विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। जीडीएआई द्वारा गेम डेवलपमेंट की मूलभूत जानकारी और गेम जैम में भाग लेने की प्रक्रिया से संबंधित परिचयात्मक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इससे यह पहल विद्यार्थियों और पहली बार गेम डेवलपमेंट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ अनुभवी क्रिएटर्स के लिए भी सुलभ होगी।

प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन ने कहा कि मध्य प्रदेश में युवा, रचनात्मक और तकनीक-आधारित प्रतिभाओं का एक बड़ा समूह है। इसका उद्देश्य प्रतिभाओं को प्रयोग करने, नवाचार करने और उभरते उद्योगों के लिए निर्माण करने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि गेमिंग तकनीक, डिजाइन, कला और कहानी कहने को एक साथ लाता है और इसमें उद्यमिता तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने की क्षमता है। 'एमपी गेम उड़ान' के माध्यम से प्रदेश के क्रिएटर्स की पहचान कर उन्हें उद्योग विशेषज्ञता से जोड़ने और मध्यप्रदेश में मजबूत गेम डेवलपमेंट समुदाय के निर्माण की शुरुआत की जाएगी।

राजनाथ ने की श्रीलंका की प्रधानमंत्री से भेंट

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच विकासात्मक सहयोग, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और श्रीलंका साझी विरासत वाले लोकतांत्रिक देश और करीबी पड़ोसी हैं। दोनों देशों को क्षेत्र में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विकास की साझा सोच के साथ आगे भी मिलकर काम करना चाहिए।

उच्च न्यायालय की नई वेबसाइट में तकनीकी खामियों पर जताई नाराजगी

आईटी स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवाल, 7 दिन में जांच रिपोर्ट तलब

जबलपुर, देशबन्धु। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नई वेबसाइट में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गंभीर नाराजगी जताई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंद्र कुमार सिंह की पीठ ने पारित आदेश में कहा कि वेबसाइट ई-हियरिंग को सपोर्ट नहीं कर रही है और इसमें कई तकनीकी गड़बड़ियां हैं। इन खामियों के कारण न्यायिक समय बर्बाद हुआ।

पीठ ने कहा कि वेबसाइट के संबंध में आईटी स्टाफ की अक्षमता को गंभीरता से लिया जा रहा है। आदेश में मुख्य न्यायाधीश से संबंधित आईटी स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है। पीठ ने रजिस्ट्रार (आईटी-सीएसए) केएस कुशवाहा को विस्तृत जांच कराने और यह बताने के निर्देश दिए कि हाई कोर्ट के कामकाज में बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है। दोषी पाए जाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई कर सात दिन के भीतर पीठ को रिपोर्ट देने को कहा गया है। पीठ ने हाई कोर्ट

के आईटी सिस्टम की स्वतंत्र जांच के लिए टीसीएस, इंफोसिस या एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के विशेषज्ञों की टीम गठित करने का निर्देश दिया है। टीम में भारत सरकार के सी-डॉट और मासकॉम के अधिकारी भी शामिल किए जा सकते हैं। तीसरे पक्ष का यह ऑडिट 30 दिन में पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।

कोर्ट रोड पर देर रात स्वास्थ्य विभाग की छापामार कार्रवाई

मिली एक्सपायरी दवाईयां, दुकान की सील

शिवपुरी,देशबन्धु। शहर के कोर्ट रोड स्थित शिव मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देर रात छापामार कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। निरीक्षण के दौरान दुकान में एक्सपायरी डेट का प्रोटीन पाउडर एवं दवाएं विक्रय के लिए रखी हुई पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी के अनुसार कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को कोर्ट रोड स्थित शिव मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी डेट की दवाओं एवं अन्य खाद्य औषधि सामग्री के विक्रय की शिकायत की जांच के लिए भेजा गया था। निर्देश मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋक्षीश्वर के नेतृत्व में टीम देर रात मेडिकल स्टोर पर पहुंची और दुकान का निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण के दौरान टीम को दुकान में एक्सपायरी डेट का प्रोटीन पाउडर तथा एक्सपायरी दवाएं विक्रय के लिए उपलब्ध मिलीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर मौजूद सामग्री की जांच की और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

कार्रवाई के दौरान फार्मासिस्ट बालेंदु रघुवंशी एवं एएसओ आईपी गोयल सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। वहीं, कार्रवाई के दौरान शिवपुरी तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण भी

मौके पर उपस्थित रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में शिव मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब यह भी जांच का विषय है कि एक्सपायरी डेट की दवाएं और प्रोटीन पाउडर मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुंचे और इन्हें विक्रय के लिए क्यों रखा गया था। विभाग द्वारा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई ने एक बार फिर मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और भंडारण व्यवस्था की निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि विभाग की ओर से जिले के अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी इसी तरह की जांच और कार्रवाई की जाती है या नहीं।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से महल कॉलोनी में हड़कंप

शिवपुरी, देशबन्धु। शहर की महल कॉलोनी स्थित यूनियन बैंक वाली गली में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने को मिली। गली में घरों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित अमले ने अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान घरों के सामने बने अस्थायी निर्माण और रास्ते में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाया गया।

बताया जा रहा है कि यूनियन बैंक वाली गली में कई घरों के सामने लोगों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार जगह घेरकर अतिक्रमण कर लिया गया था। इसके चलते गली की चौड़ाई प्रभावित होने के साथ ही आम लोगों के आवागमन में भी परेशानी सामने आ रही

थी। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए घरों के आगे से अतिक्रमण हटाया गया।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान टीम ने गली में घर-घर के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिन स्थानों पर रास्ते की जगह घेरकर निर्माण अथवा अन्य सामान रखा गया था, उसे हटाया गया।प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गली में आवागमन के लिए जगह खुली नजर आई। स्थानीय लोगों के बीच भी कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी रही।

शहर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बीच महल कॉलोनी की यूनियन बैंक वाली गली में हुई कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। प्रशासन का यह अभियान शहर की अन्य गलियों और सार्वजनिक रास्तों तक पहुंचता है या नहीं, इस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

संस्कारधानी का सुषमा सावंत ने बढ़ाया मान, छग में आज संभालेगी न्याय की कमान

जबलपुर, देशबन्धु। संस्कारधानी की धरती ने जिस बेटी को शिक्षा और संस्कार दिए, अब वही बेटी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायिक पीठ पर बैठकर न्याय की नई जिम्मेदारी संभालेगी। शहर में पढ़ी-लिखीं सुषमा सावंत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुषमा सावंत की इस नियुक्ति ने संस्कारधानी का मान बढ़ाते हुए शहर को गौरान्वित किया है।

दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। वे आज 10 सितंबर को बिलासपुर में शपथ लेंगी। सुषमा सावंत का जन्म 24 नवंबर 1969 को छिंदवाड़ा में हुआ। वे जबलपुर के कृपा शंकर वर्मा की पुत्री हैं। जानसन गर्ल्स स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा के बाद एमएच कालेज से बीएससी और हितकारिणी कालेज से विधि स्नातक किया। 1994 में सिविल जज के रूप में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया। विवाह के बाद छत्तीसगढ़ को कर्मभूमि बनाया। महासमुंद, बिलासपुर और राजनांदगांव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहीं। बिलासपुर कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की निदेशक का दायित्व भी संभाला। मई 2012 में विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अतिरिक्त सचिव बनीं। अप्रैल 2024 में राजनांदगांव की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 13 अक्टूबर 2025 से विभाग की प्रमुख सचिव हैं। इस पद पर पहुंचने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी हैं।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर पुलिस ने की कार्रवाई

फिल्मी अंदाज में आईफोन लेकर भागे आरोपी गिरफ्तार, दुकान पर आए थे ग्राहक बनकर

शिवपुरी, देशबन्धु। शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र में एक शातिर चोर ने फिल्मी अंदाज में जो कारनामा किया, वह अब चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पुलिस के लिए भले ही चुनौती खड़ी की थी, लेकिन खाकी की मुस्तैदी ने इस मामले का चंद दिनों में ही पर्दाफाश कर दिया। घटना गत 3 सितंबर की है, जब कमलागंज घोसीपुरा के रहने वाले अरशद खान अपनी मोबाइल दुकान पर बैठे थे। तभी एक ग्राहक बनकर आया शातिर शख्स दुकान पर पहुंचा और मोबाइल दिखाने की मांग करने लगा। दुकानदार जैसे ही मोबाइल दिखाने में मशगूल हुआ, शातिर युवक दो कीमती आईफोन उठाकर पलक झपकते ही बाहर भागा और सड़क पर पहले से ही बाइक लेकर खड़े अपने साथी की गाड़ी पर बैठकर नौ दो ग्यारह हो गया।

मामला तूल पकड़ते ही पुलिस अधीक्षक यांगचैन डोलकर भूटिया ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के कड़े निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसपी शिवपुरी के मार्गदर्शन में पुलिस की भागदौड़ रंग लाई और महज़ कुछ ही दिनों में पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान श्योपुर जिले के करहाल इलाके के रहने वाले रघुबिन्दर सिंह और कान्हा आदिवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी गए आईफोन 13 और आईफोन 14 प्रो सहित घटना में प्रयुक्त की गई रायडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, जिनकी कुल कीमत करीब 90,000 रुपये है। बुधवार की दोपहर 3 बजे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस खुलासे को अंजाम देने में थाना प्रभारी अवनीश सिंह राठौड़ और उनकी टीम के अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका सराहनीय रही।

शराब मुक्त गांव बनाने की मांग

शराब बिक्री के विरोध में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

शिवपुरी, देशबन्धु। खोड़ चौकी क्षेत्र के ग्राम बैरागढ़ में बुधवार सुबह शराब की बिक्री के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। गांव में शराब की बिक्री बंद कराने और शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर सिरसौद-खोड़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुए प्रदर्शन के चलते मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा।

ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटे रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में खुलेआम शराब की बिक्री होने से सामाजिक और पारिवारिक माहौल लगातार खराब हो रहा है। शराब के नशे में आए दिन घरों में विवाद की स्थिति बनती है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि उनके पति मजदूरी कर जो पैसा घर लेकर आते हैं, उसका बड़ा हिस्सा शराब में खर्च हो जाता है। इसके बाद घरों में आर्थिक तंगी के साथ-साथ विवाद और मारपीट की स्थिति भी

उत्पन्न होती है। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि शराब की वजह से कई परिवारों की खुशियां प्रभावित हो रही हैं। मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले लोगों की कमाई शराब में खर्च होने के कारण बच्चों की पढ़ाई, भोजन और अन्य जरूरी जरूरतों पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब की बिक्री पर रोक लगने से परिवारों की स्थिति में सुधार आ सकता है।

इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद करते हुए शराब की दुकान हटाने की मांग की है।प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से बैरागढ़ गांव में शराब की बिक्री बंद कराने और शराब की दुकान हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने गांव को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं और इसके लिए सामूहिक रूप से आंदोलन कर रहे हैं।

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। चक्का जाम की सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस की नजर भी पूरे घटनाक्रम पर बनी रही। बैरागढ़ में शराब के विरोध में ग्रामीणों का सड़क पर उतरना केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि गांवों में शराब की बिक्री से जुड़े सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों को भी सामने लाता है। अब ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन और आबकारी विभाग क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी।

राजधानी

सार-समाचार

बीएमएचआरसी में प्रतिरक्षा विज्ञान पर दो दिवसीय कार्यशाला शुरु

भोपाल, देशबन्धु। भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में इंडियन इम्यूनोलॉजी सोसाइटी के तत्वावधान में प्रतिरक्षा निदान और टीका विकास विषय पर दो दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा एवं व्यावहारिक कार्यशाला शुरू हुई। इसमें करीब 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. नरेंद्र कोतवाल ने कहा कि प्रतिरक्षा विज्ञान में निदान और उपचार दोनों महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने शोधार्थियों से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समर्पण के साथ अनुसंधान करने का आह्वान किया। डॉ. माधवनंद कर ने कहा कि सही समय पर सटीक निदान और उपचार मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों ने बदलते रोगों से निपटने में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने और नई निदान एवं उपचार तकनीकों पर शोध की जरूरत बताई। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के बीच समूह चर्चा भी हुई।

भीतर की शांति खोजने की राह

भोपाल, देशबन्धु। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारियों के बीच तनाव व मानसिक अशांति बढ़ रही है। नौकरी, परिवार, आर्थिक चिंता और भविष्य की अनिश्चितता से व्यक्ति बाहरी सुविधाओं के बावजूद भीतर से परेशान है। ऐसे समय में अघोर दर्शन सहजता, करुणा और आत्मिक संतुलन का मार्ग दिखाता है। परम पूज्य अघोरेश्वर अलख राम जी के संदेश में अघोर को भय, भेदभाव और घृणा से मुक्त जीवन बताया गया है। शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देना, विचारों को साक्षी भाव से देखना, संतुलित आहार लेना और नशे से दूर रहना मन को स्थिर करने में सहायक माना गया है। अघोर परंपरा में सेवा को साधना का स्वरूप दिया गया है। जरूरतमंदों की सहायता, माता-पिता की सेवा और प्रत्येक जीव के प्रति करुणा को जीवन का आधार माना गया है। संदेश है कि शांति बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर है।

कर्नाटक की तर्ज पर टीईटी से मिले राहत

भोपाल, देशबन्धु। शिक्षक संघ एकीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य डॉ. रणजीत मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष रमेशचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से पूरी तरह छूट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता पूरी कर नियमित नियुक्त हुए शिक्षकों पर बाद में नई पात्रता परीक्षा थोपना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी टीईटी से राहत देने की मांग की ज्ञापन में ई-अटेंडेंस की तकनीकी समस्या, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण, पुरानी पेंशन, शिक्षा विभाग में रिक्त पद, शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ और शिक्षा बजट बढ़ाने सहित छह अन्य मुद्दे भी उठाए गए।

जिला पंचायत की साधारण सभा में अफसरों पर बरसे जनप्रतिनिधि

स्वास्थ्य-शिक्षा की बदहाली पर 7 दिन में सुधार की चेतावनी

भोपाल, देशबन्धु। जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में बुधवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली और वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को घेरा। करीब तीन घंटे चली बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं होने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर की अध्यक्षता और मुख्य कार्यपालन अधिकारी इला तिवारी की मौजूदगी में हुई बैठक में अधिकारियों से समस्याओं के समाधान की समयसीमा भी पूछी गई।

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सदस्य विनय मेहर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और कर्मचारियों की कमी दूर नहीं हुई तो सात दिन बाद उनके कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। मेहर ने बैरसिया स्वास्थ्य विभाग की खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्पा गुरु को हटाने का प्रस्ताव भी रखा।

प्रस्ताव पर जिला पंचायत सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सीएमएचओ ने 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने की बात कही।

स्कूलों में बालिकाओं के शौचालय पर सवाल

सदस्य मेहर ने ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि करीब 70 प्रतिशत स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुचारू नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने और सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

पेयजल व्यवस्था पर चर्चा के दौरान उन्होंने नल-जल योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही बरती जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी जनप्रतिनिधियों ने सवाल किए। सदस्यों ने कहा कि रखरखाव के लिए सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं बिजली के तार टूटे या लटके हुए हैं तो कहीं आवश्यक केबल उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों से व्यवस्था सुधारने की मांग की गई।

अधूरे पंचायत भवनों का मुद्दा उठा

फंदा जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने वर्षों से अधूरे पड़े पंचायत भवनों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए राशि जारी होने के बावजूद कई भवन अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को अंत्येष्टि के लिए वन विभाग से लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। विधायक प्रतिनिधि दीपक गुर्जर ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ मामलों में ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से डराया-धमकाया जा रहा है। उन्होंने एक गांव में पुलिस के साथ आधी रात कार्रवाई किए जाने का मुद्दा उठाया और बैरसिया क्षेत्र के रेंजर से जवाब मांगा। वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी मनमोहन सिंह जाटव ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

उपाध्यक्ष समेत 4 सदस्य अनुपस्थित

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट और तीन सदस्य अनुपस्थित रहे। सदस्य चंद्रेश राजपूत ने कहा कि बैठकों में जनप्रतिनिधि लगातार समस्याएं उठाते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसी कारण उपाध्यक्ष भी बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में सदस्य विक्रम भालेश्वर, बीजिया राजोरिया, गंगा मालवीय सहित सदस्य प्रतिनिधि सुरेश सिंह राजपूत, विनोद राजोरिया, मिश्रीलाल मालवीय और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

फंदा जनपद में योजनाओं की समीक्षा

इसी दिन जनपद पंचायत फंदा में भी सामान्य प्रशासन एवं साधारण समिति की बैठक हुई। अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवानी मिश्रा ने एजेंडा प्रस्तुत किया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनपद उपाध्यक्ष मलखान सिंह ठाकुर, सदस्य संतोष प्रजापति और राहुल मंडलोई सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

मिसरोद की कॉलोनी में आधी रात हंगामा, 6 कारों को मारी टक्कर

भोपाल, देशबन्धु। मिसरोद थाना क्षेत्र की फारच्यून हेरीटेज कॉलोनी में मंगलवार रात एक युवक ने तेज रफ्तार थार चलाकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि युवती से विवाद के बाद युवक किराये की थार लेकर कॉलोनी पहुंचा और गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गया। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी 6 से अधिक कारों को टक्कर मार दी। घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

घटना रात करीब सा? 10 बजे की बताई जा रही है। बुधवार को सामने आए सीसीटीवी फुटेज में थार तेज रफ्तार से कॉलोनी में आती और वाहनों को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। बेकाबू वाहन को देखकर रहवासियों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। सुरक्षा कर्मचारियों ने गेट बंद करने का प्रयास किया, लेकिन युवक गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गया।

घटना के बाद रहवासियों ने पुलिस में शिकायत की। कॉलोनी निवासी कमल सिंह सोलंकी की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार के अनुसार आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों और किराये पर ली गई थार के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

10 डिजिटल स्टूडियो में तैयार हो रहे वीडियो व्याख्यान

भोपाल, देशबन्धु। उच्च शिक्षा को तकनीक आधारित और विद्यार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ई-ज्ञानसेतु के माध्यम से डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को ई-ज्ञानसेतु पर ई-कंटेंट के अपलोड एवं प्रकाशन कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा और संस्कृति से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए संस्कृत, मराठी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में भी सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए।

शहर के 50 इलाकों में आज बिजली कटौती

भोपाल, देशबन्धु। बिजली कंपनी द्वारा गुरुवार को शहर के करीब 50 इलाकों में रखरखाव कार्य किया जाएगा। इसके चलते अलग-अलग क्षेत्रों में 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक शाहपुरा, अशोका सोसायटी, विवेक अपार्टमेंट और आसपास बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बड़वई, न्यू कोहेफिजा, पटेल नगर, रायसेन रोड, आईबीडी परिसर, एलेक्सर गार्डन, सिग्मा ग्रीन और कम्फर्ट हाइट्स में आपूर्ति प्रभावित होगी। इसी अवधि में अशोका गार्डन, लक्ष्मी नगर, सुंदर नगर, रजत नगर, कल्पना नगर, सहकारी परिसर, प्रगति नगर, अमृत कॉम्प्लेक्स, अशोक विहार और दसमेश नगर में भी बिजली बंद रहेगी। सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक कोटरा और पलकमती पार्क, जबकि सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बागसेवनिया, अरविंद विहार, पुरानी बस्ती और महेशमती में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक हिनोतिया, सुहागपुर, फैथकलां, पिपलिया केशो, गुरारी घाट, रतनपुर सड़क और नरेला हनुमंत सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।

पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी प्रारम्भ

मप्र में साढ़े 7 हजार आरक्षकों की भर्ती, 22 से आवेदन शुरु

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से शुरू होंगे और अभ्यर्थी 6 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की सुविधा 11 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। संभावित लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को प्रदेश के 55 जिलों में से अपनी पसंद की इकाई का चयन करना होगा। जिस इकाई में नियुक्ति मिलेगी, वहां कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही दूसरी इकाई में स्थानांतरण किया जा सकेगा। कुल 7,500 पदों में विशेष सशस्त्र बल के 700 और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आरक्षक के 6,800 पद शामिल हैं। आवेदन के समय अभ्यर्थी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह किस संवर्ग के आरक्षक पद के लिए आवेदन कर रहा है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासकीय रेल पुलिस की भोपाल, इंदौर और जबलपुर इकाइयों में भी की जाएगी।

परीक्षा केंद्र पर आधार आधारित जैवमितीय सत्यापन होगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्राप्त अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।

शारीरिक मापदंड: विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर आरक्षक के अन्य संवर्गों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर निर्धारित है। वहीं सीने की माप भी निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। विशेष सशस्त्र बल के लिए भी अलग शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान रंगीन फोटो, हस्ताक्षर और हाथ से लिखा एक अनुच्छेद की स्कैन प्रति लगानी होगी। पोलेराइड फोटो मान्य नहीं होंगे। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आठवीं, दसवीं या बारहवीं की अंकसूची तथा जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बोनस अंकों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को एनसीसी अथवा संबंधित प्रमाणपत्र भी लगाने होंगे।

परीक्षा शुल्क के अलावा मंडल और विभागीय शुल्क तथा आवेदन माध्यम के अनुसार पोर्टल शुल्क भी निर्धारित किया गया है। आवेदन

विद्यालयों में बिजली पहुंचाने की मुहिम तेज

1,763 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन का काम पूरा

भोपाल, देशबन्धु। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण का काम तेज किया है। कंपनी के कार्यक्षेत्र के 24 जिलों में ऐसे विद्यालयों को बिजली से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जहां अब तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

31 अगस्त 2026 तक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा चिन्हित 2,752 गैर-विद्युतीकृत विद्यालयों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। सर्वेक्षण में 394 विद्यालयों में पहले से बिजली कनेक्शन पाए गए। कुछ विद्यालयों में भवन उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य कारणों से तत्काल कनेक्शन देना संभव नहीं पाया गया।

सर्वेक्षण के आधार पर 2,254 विद्यालयों में बिजली पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार की गई। इनमें 814 विद्यालय ऐसे थे, जहां बिना अतिरिक्त विस्तार के सीधे कनेक्शन दिया जा सकता था। इन सभी विद्यालयों को बिजली से जोड़ा जा चुका है। वहीं 1,440 विद्यालयों में विद्युत लाइन और नेटवर्क विस्तार की जरूरत चिन्हित हुई। इनमें से 949 विद्यालयों में विस्तार कार्य पूरा कर कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है।

इस प्रकार लक्षित 2,254 विद्यालयों में से 1,763 विद्यालयों में विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, जो करीब 78 प्रतिशत है। शेष 491 विद्यालयों में भी आवश्यक कार्यवाही जारी है। पूर्ण किए गए 1,763 कनेक्शन कार्यों में से 1,667 के कार्य संबंधी अभिलेख भी तैयार किए जा चुके हैं।

कंपनी द्वारा विद्यालयों के विद्युतीकरण में केवल कनेक्शन देने के बजाय आवश्यक विद्युत लाइन और नेटवर्क विस्तार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में बिजली उपलब्ध होने के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सकेगा। शेष विद्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से बिजली सुविधा से जोड़ने का काम जारी है।

सरकार ने मानी मांगे, मानदेय बढ़ाने पर खत्म हुआ 3 दिन का आंदोलन

काम पर लोटे जूडा अब मिलेंगे साढ़े 21 हजार

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 3 दिन से आंदोलन कर रहे इंटर्न चिकित्सकों ने बुधवार को सरकार से सहमति बनने के बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सहमति से इंटर्न चिकित्सकों का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाकर 21,500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सोमवार को प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग और पानी की बौछार किए जाने के मामले में प्रारंभिक रूप से सामने आए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है। मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है।

बुधवार को दिनभर आंदोलन के कारण भोपाल के हमीदिया अस्पताल सहित प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमीदिया अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग की सेवाएं प्रभावित रहीं। सुबह 9 से 10 बजे तक विभाग बंद रहा। मरीजों की भीड़ को देखते हुए सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक इसे खोला गया, लेकिन चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से मरीजों को परेशानी हुई। इस दौरान करीब 500 मरीज पहुंचे, जबकि सामान्य दिनों में यहां करीब 3,000 मरीज बाह्य रोगी विभाग में आते हैं।

सीहोर से आए विजय सिंह ने बताया कि उन्हें करीब एक महीने से यकृत की परेशानी है और अब गुर्दे में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने चिकित्सक नहीं मिलने पर परेशानी जताई। विदिशा से भेजी गईं कल्पना राय सीने में दर्द की शिकायत लेकर सुबह से अस्पताल में इलाज के लिए भटकती रहीं। वहीं शिवशक्ति नगर की चंदा साहू को पैर में फ्रैक्चर के कारण चिकित्सक से मिलने का समय मिला था, लेकिन चिकित्सक नहीं मिलने से उन्हें बिना इलाज लौटना पड़ा। सिंगरौली से करीब 720 किलोमीटर की दूरी तय कर दांत का इलाज कराने आए एक मरीज ने भी दो दिन से अस्पताल के चक्कर लगाने के बावजूद उपचार नहीं मिलने की बात कही।

हमीदिया में सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 40 नियोजित शल्यक्रियाएं होती हैं, लेकिन बुधवार को ऐसी एक भी शल्यक्रिया नहीं हुई। आवश्यक आपात सेवाएं और गहन चिकित्सा जैसी सेवाएं जारी रहीं। वरिष्ठ चिकित्सकों ने मरीजों को संभाला।

इधर, कमला पार्क के पास सड़क पर बैठे इंटर्न चिकित्सकों ने सरकार से सहमति बनने के बाद प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद सड़क खाली कर यातायात सामान्य किया गया। आंदोलन के दौरान चिकित्सक 30,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग कर रहे थे। सरकार द्वारा 21,500 रुपए करने के निर्णय पर चिकित्सक प्रतिनिधियों ने संतोष जताया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घायल छात्रों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पानी की बौछार किए जाने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। सरकार और चिकित्सक प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनने के बाद 3 दिन चला आंदोलन समाप्त हो गया।

जगदीश मित्तल की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आज

भोपाल, देशबन्धु। राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक अध्यक्ष जगदीश मित्तल 'बाबू जी' के निधन पर मध्य प्रदेश इकाई द्वारा आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। दुष्यंत संग्रहालय, शिवाजी नगर में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होने वाली सभा में साहित्यकार, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी.431/ 84

श्री ओसवाल स्थानकवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

29, हमीदिया रोड, भोपाल

क्र.: वार्षिक साधारण सभा/2026 दि.: 09.09.2026

वार्षिक साधारण आमसभा की सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **श्री ओसवाल स्थानकवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल मध्य प्रदेश** की साधारण आमसभा **दिनांक 25.09.2026 दिन शुक्रवार को समय प्रातः 10:00 बजे**, स्थान **संत निवास, विमल साडी एम्पोरियम के पास, न्यू मार्केट भोपाल में** आयोजित की गई है। आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। इस संबंध में सूचना डाक द्वारा पृथक से भेजी जा चुकी है।

(सुशील कुमार बाफना)
अध्यक्ष, श्री ओसवाल स्थानकवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

In the Court of III Civil Judge Class-I, District Court, Ujjain
Presiding Officer : श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000611/2023)

डॉ. मेल्कीसदेक देवशिखामणी.....वादी
Vs
एमपीपीकेवीवीसी लि. मक्सी रोड उज्जैन.....प्रतिवादी
Process Id- 2026
पेशी दिनांक.- 15/09/2026

प्रेषिती- सेशन अब्राहम पिता के अी अब्राहम पता-ए-53 ओल्ड मिनल रेसीडेंसी जेके रोड गोविन्दपुरा, भोपाल म.प्र.

यह कि प्रार्थी/वादी डॉ. मेल्कीसदेक देवशिखामणी ने आपके विरूद्ध वाद वास्ते स्थायी निशेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रकरण में विचाराधीन रहते वादी ने आप सेशन अब्राहम पिता के.ई.अब्राहम निवासी--ए-53 ओल्ड मिनल रेसीडेंसी जेके रोड गोविन्दपुरा भोपाल को प्रकरण में प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें । आज तारीख 13 August 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है ।

सील

न्यायाधीश -(सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ
खण्ड, उज्जैन म.प्र.

कृपया ध्यान दें-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, इटारसी (म.प्र.)

E-mal-cmoitarsi@mpurban.gov.in
पता- भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पास सिंधी कालोनी इटारसी पिन-461111

क्र./न.प./स्टोर शाखा/2026/ 2234 इटारसी, दिनांक 07.09.2026

ई निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य हेतु ऑनलाईन टेंडर शासन के टेंडर पोर्टल वेबसाईट https:\\www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर नंबर	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	प्रारंभ तिथि अंतिम दिनांक विड खोले जाने की तिथि	टेंडर फार्म मूल्य अमानत राशि	ठेकेदार की श्रेणी कार्य अवधि
1	2026_UAD_534004_1	नवरात्रि उत्सव अंतर्गत दिनांक 11.10.2026 से 20.10.2026 तक (नवरात्रि से दशहरा उत्सव तक) स्थानीय गांधी मैदान एवं सूखा सरोवर पुरानी इटारसी मैदान पर रामलीला मंचन हेतु रामलीला मंडल उपलब्ध कराना, मंच व्यवस्था, मैदान व्यवस्था, विद्युत साज सज्जा व्यवस्था, उच्च कोटि माईक व्यवस्था एवं अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्था का कार्य तथा स्थानीय द्वारिकाधीश मंदिर में रासलीला की संपूर्ण व्यवस्था का कार्य एवं शेर नृत्य एवं ढोल प्रतियोगिता कराने का कार्य।	18,75,000/-	05.09.2026 05.10.2026 07.10.2026	2000/- 14,065/-	-

शर्तें एवं जानकारी नगरपालिका की स्टोर शाखा से प्राप्त की जा सकती है। संशोधन होने पर केवल वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, इटारसी

देशबन्धु

भोपाल, गुरुवार, 10 सितम्बर 2026

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

नस्लीय नफरत का शिकार समाज

भारत जैसे उदार समझे जाने वाले देश में नफरत को इस कदर बढ़ावा दिया जा चुका है कि आम जनता के बीच से ही कुछ लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने में नहीं झिझक रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते दिन मणिपुर के चर्चित गिटारिस्ट और संगीत शिक्षक चोंगथाम विक्रम सिंह की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला इसका ताजा उदाहरण है। चोंगथाम विक्रम सिंह का कसूर केवल इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास शोर मचा रहे कुछ लोगों को टोका। हो सकता है टोकने का यह मामला हत्या तक नहीं पहुंचता, लेकिन चोंगथाम विक्रम सिंह का पूर्वोत्तर से होना क्या इस हत्या का एक अहम कारक बना है, इस सवाल पर गंभीरता से सोचना होगा। राज्य और केंद्र की सत्ता पर बैठी भाजपा सरकार ने तो इसमें नस्लीय नफरत के नजरिए तो फौरन खारिज कर दिया है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, जो खुद पूर्वोत्तर से आते हैं, का कहना है कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, चोंगथाम विक्रम सिंह पूर्वोत्तर से हैं, ऐसा न देखकर ये देखना चाहिए कि वे भारतीय थे।

ऐसी बात सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगती है और कायदे से होना भी यही चाहिए, लेकिन किरण रिजिजू को ईमानदारी से बताना चाहिए कि क्या मोदी सरकार में ऐसा ही होता है। क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पूर्वोत्तर के लोगों को लगातार नस्लीय हिंसा या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। उत्तराखंड में ही पिछले साल 9 दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा को चाइनीज़ और मोमो जैसे अपमानजनक शब्द कहते हुए पीट-पीट कर मार दिया गया था। इसलिए, विक्रम सिंह मामले में यह पड़ताल भी करनी ही चाहिए कि इसके पीछे नस्लीय हिंसा थी या नहीं।

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दुखद मौत के लिए जिम्मेदार हमले की घटना से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस घटना ने राजधानी में उत्तर-पूर्वी लोगों द्वारा झेली गई क्रूरता के दर्दनाक घावों को एक बार फिर से हरा कर दिया है। इसी तरह मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से गहन जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी समेत सामने आ रहे सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ तेजी से उचित कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित को जल्द न्याय मिलना चाहिए। क्या भाजपा इन लोगों के बयानों को भी राजनीति बताएगी, क्योंकि ये तो एनडीए नेताओं के ही बयान हैं।

वैसे ऐसी हरेक घटना पर राहुल गांधी की बात ही याद आती है कि नफरत का केरोसिन छिड़का जा चुका है और चिंगारी लगाने की देर है। कुछ वक्त पहले तक शायद इस चिंगारी को सुलगाने वाले लोगों को कानून का कुछ डर तो रहता ही होगा, लेकिन अब ये बेखौफ आग लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे आपराधिक तत्व कहीं न कहीं आश्वस्त हैं कि सत्ता में बैठे लोग उन्हें बचा ही लेंगे। दिल्ली में एक दलित को पीटने वाले स्वतंत्र भारद्वाज ने यही कहा था कि उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी, क्योंकि मोदीजी उसके बड़े भाई हैं। देश में अब हर गली-कूचे में स्वतंत्र भारद्वाज जैसे लोगों का बढ़ जाना समाज के लिए काफी चिंताजनक है। क्योंकि अब बात केवल हिंदू-मुसलमान, दलित-स्वर्ण तक सीमित नहीं रही, समूचे समाज को यह नफरत लील रही है।

गौरतलब है कि 54 वर्षीय चोंगथाम विक्रम सिंह पिछले 17 वर्षों से दिल्ली में संगीत सिखाने का काम कर रहे थे। उन्हें मणिपुर के संगीत जगत में एक चर्चित गिटारिस्ट और पश्चिमी संगीत के प्रमुख कलाकारों में गिना जाता था। रविवार रात करीब 11:30 बजे उन के घर के पास कुछ लोग शोर-शराबा कर रहे थे। इनमें आसपास के ढाबों में काम करने वाले डिलीवरी और पैकेजिंग कर्मचारी भी शामिल थे। चोंगथाम विक्रम सिंह ने उन लोगों से शोर मचाने से मना किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सिंह अपने घर की ओर भागे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया और इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुंचकर उनके साथ उनको बेरहमी से पीटा। उनकी पत्नी और बेटे ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में तो लिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार समेत पूर्वोत्तर के लोगों को नाइंसाफी की आशंका है। यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी के साथ-साथ पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा और नस्ली भेदभाव से जुड़ी व्यापक समस्या पर भी सरकार ठोस कार्रवाई करेगी? क्योंकि अब तक ऐसी कोई मिसाल मोदी सरकार ने नहीं दी है।

नरेन्द्र मोदी को अपने प्रचार कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक पिता की अपने ही घर के बाहर, देश की राजधानी में हत्या कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी कई घटनाओं के बाद दिल्ली में रहने वाला पूर्वोत्तर का हर परिवार आज खुद से पूछ रहा है-'क्या हम यहां सुरक्षित हैं?' राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह का गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए, क्या कर रहे हैं, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ? तत्काल जांच होनी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

राहुल गांधी तो अपनी जवाबदेही निभा रहे हैं, सरकार कब काम करना शुरु करेगी इसका इंतजार है।

सिमोन द बुवा के देश में नारी उत्पीड़न

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

20वीं सदी के फ्रांस में वैश्विक नारीवाद की अहम किरदार थीं- सिमोन द बुवा। नारी सशक्तीकरण पर उनके मौलिक और क्रांतिकारी विचारों पर दुनिया में आज भी मंथन होता है। सिमोन द बुवा की सुप्रसिद्ध किताब है 'द सेकंड सेक्स'। इस किताब में सिमोन कहती हैं कि औरत पैदा नहीं होती है, बल्कि समाज औरत को गढ़ता है। वह बार-बार इस पर ज़ोर देती हैं कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, लड़कियों को मजबूर करता है 'स्त्री' बनने के लिए। सिमोन का कहना है कि इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि हमारे धर्म में औरतों की भी पूजा होती है। धर्म तो वास्तव में आदमियों के द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है औरतों पर शासन करने का।

फ्रांस ने दुनिया को केवल सिमोन द बुवा जैसी अद्भुत नारीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं दी, बल्कि उनसे पहले फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अद्भुत विचार दुनिया को दिया। यही लोकतंत्र की नींव बना और भारत के संविधान की बुनियाद भी इसी पर टिकी है। अब इसी फ्रांस में मानवता के लिए जरूरी इन मूल्यों पर कुठाराघात करने का काम किया है बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था यानी बीएपीएस ने। पाठकों को बता दूं कि गुजरात के बोचासन से इस संस्था का संबंध है। अक्षरधाम मंदिर इसी संस्था का है। हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बीएसपीएस के एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हार्दिक खुशी जाहिर की थी।

इस संस्था के कहां कितने मंदिर बनते हैं यह अलग मुद्दा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस संप्रदाय में महिला से दूरी बनाए रखने, महिला के साथ अकेले में बात न करने आदि के नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन इससे जुड़े लोग करते हैं। यह भी उनका निजी मामला है कि वे महिला से बात करें न करें। लेकिन पेरिस में मंदिर उद्घाटन के लिए संस्था का जो प्रतिनिधि मंडल पेरिस गया था, उसमें करीब 100 लोग एफिल टावर देखने पहुंचे तो उनके कहने पर वहां पहले बाकायदा महिला कर्मचारियों को हटाया गया।

एफिल टावर की कर्मचारी यूनियन की प्रतिनिधि डायने डावोइन के अनुसार, जब प्रतिनिधि मंडल टावर के अंदर से गुजर रहा था, तब महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों से हटने के लिए कहा गया ताकि उनकी जगह पुरुष कर्मचारी खड़े हो सकें। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ महिलाओं को अपनी पोस्ट छोड़कर दूसरे हिस्सों में जाने के लिए कहा गया, जबकि कुछ स्थानों पर उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को तैनात किया गया। महिला कर्मचारियों को प्रतिनिधि मंडल की मौजूदगी के दौरान कुछ खास इलाकों में जाने या उन्हें पार करने से भी रोका गया।

> **जिस फ्रांस में सिमोन द बुवा ने पुरुष और स्त्री समानता की मशाल बुलंद की, धार्मिक व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई, उसी फ्रांस में सौ साल बाद लैंगिक भेदभाव की ऐसी घटना घटेगी, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। इस घटना से आहत एफिल टावर के कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया, जिसके चलते टावर को आगंतुकों के लिए बंद रखना पड़ा।**

जिस फ्रांस में सिमोन द बुवा ने पुरुष और स्त्री समानता की मशाल बुलंद की, धार्मिक व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई, उसी फ्रांस में सौ साल बाद लैंगिक भेदभाव की ऐसी घटना घटेगी, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। इस घटना से आहत एफिल टावर के कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया, जिसके चलते टावर को आगंतुकों के लिए बंद रखना पड़ा। गौरतलब है कि एफिल टावर दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और इसकी वेबसाइट के अनुसार यहां हर साल करीब 70 लाख लोग आते हैं। फिलहाल पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोआर ने मामले की जांच कराने की घोषणा की है। जबकि एफिल टावर का संचालन करने वाली कंपनी एसईटीई ने माना कि हिंदू प्रतिनिधि मंडल की ओर से महिलाओं के साथ बातचीत या संपर्क को सीमित रखने की मांग की गई थी। कंपनी ने कहा कि ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। एसईटीई के अध्यक्ष एरियल वेल ने इसे अस्वीकार्य बताया और कहा कि एफिल टावर फ्रांस के गणतांत्रिक मूल्यों तथा महिला और पुरुषों की समानता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था उसके मूल्यों और लैंगिक समानता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी तथा मामले में जांच की जाएगी। वहीं फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष याएल ब्राउन-पिवे ने भी घटना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों की मांग पूरी करने के लिए महिलाओं को पीछे हटने या सार्वजनिक जीवन से 'अदृश्य' होने के लिए नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि दूसरे लोगों का स्वागत करने का अर्थ यह नहीं है कि फ्रांस अपने मूल्यों से समझौता करे।

फ्रांस की समानता मंत्री ऑरोर बर्जे ने भी कहा कि फ्रांस में महिलाओं से खुद को 'मिटा देने' या पीछे हटने के लिए नहीं कहा जाता और कोई भी धार्मिक विचार गणराज्य के कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता।

फ्रांसीसी सरकार को यह देखने की भी जरूरत है कि उनके भीतर ऐसे कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने महिला से दूर रहने जैसे संकीर्णतावादी विचार को बढ़ावा देने में मदद की।

बीएपीएस का तो कहना है कि उसका प्रतिनिधि मंडल बड़ा था, इसलिए उसने एफिल टावर में व्यवस्था को बदलने कहा, लेकिन उसमें लैंगिक भेदभाव की बात नहीं थी। लेकिन जब टावर संचालन करने वाली कंपनी ही मान रही है कि बीएसपीएस की शर्तों को नहीं मानना चाहिए था, तो जरूर कहीं न कहीं लैंगिक भेदभाव हुआ ही होगा। बहरहाल फ्रांस तो इस मामले की जांच अपनी तरह से कर ही लेगा और जिस देश की बुनियाद उदार मानवतावादी मूल्यों पर पड़ी हो, वह खुद को दुरुस्त कर भी लेगा। लेकिन भारत इस वैश्विक शर्मिंदगी से कब और कैसे उबरेगा, यह एक बड़ा सवाल है।

बीएसपीएस का मंदिर पेरिस में बना तो नरेन्द्र मोदी ने इसे ग्रेट जॉय बताया था, तो क्या इस घटना के बाद उन्हें ग्रेट शेम महसूस नहीं हुई। क्योंकि बीएपीएस से उनकी नजदीकी बरसों पुरानी है। मोदी का वैवाहिक जीवन कैसा रहा और शादीशुदा होने के बावजूद वे अकेले क्यों रहते हैं, यह उनका निजी मामला है। लेकिन वैश्विक स्तर पर जब एक भारतीय धार्मिक संस्था पर महिलाविरोधी होने के आरोप लगते हैं, तो बतौर प्रधानमंत्री क्या उन्हें बीएपीएस से अपने संबंधों को स्पष्ट नहीं करना चाहिए।

वैसे बीएपीएस को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर उन्हें महिलाओं से तकलीफ है, उन्हें देखना भी उनके नियमों में गवारा नहीं है, तो फिर दुनिया भर में मंदिर बनवाने निकले ही क्यों हैं। दुनिया से महिलाओं को तो गायब नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये पूरा प्रतिनिधि मंडल चार्टर्ड फ्लाइट से पेरिस गया हो, जिसमें परिचारक ही रहे हों, परिचारिकाएं नहीं। लेकिन फिर वे पेरिस में मंदिर बनवा कर उसी फ्लाइट से भारत वापस आ जाते, उन्हें एफिल टावर या किसी भी विश्वप्रसिद्ध स्थल को देखने की जरूरत ही क्या है।

हमेशा की तरह इस बार भी इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोई बयान या प्रतिक्रिया नहीं आया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद को सही अर्थों में रबर स्टैम्प ही बना दिया है, जो केवल मोदी सरकार के हर फैसले, हर बात पर मुहर लगाती है। याद कीजिए कि जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था तो भाजपा ने इस बात का बड़ा श्रेय लिया था उसके शासन में देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है। लेकिन उनकी आदिवासी या महिला पहचान से देश में इन वर्गों की वस्तुस्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी सरकार में दलित, आदिवासी, मुसलमान, और महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कभी ऐसी घटनाओं पर सार्थक हस्तक्षेप किया हो, याद नहीं पड़ता।

असलियत से ज़्यादा गणितीय हो सकती है भारत की तेज़ विकास दर

■ नन्तू बनर्जी

ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, क्षेत्रीय आपूर्ति में रुकावट, कम निवेश और बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। ऐसे में, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की रिकॉर्ड वास्तविक जीडीपी विकास दर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। आर्थिक नज़रिए से भारत में वित्त वर्ष की पहली तिमाही को आम तौर पर 'धीमी विकास वाला समय' माना जाता है। देश की आधिकारिक आर्थिक विकास दर ने पहली बार एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विवाद खड़ा कर दिया है। जीडीपी की तेज़ विकास घरेलू निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने जैसे कमज़ोर संकेतकों को नहीं दिखाती है। यह ज़मीनी हकीकत को भी नहीं दिखाती है, जैसे कि ऊर्जा और खाद की ज़्यादा कीमतें, जो लगभग सभी सामान, औद्योगिक उत्पादों और लोगों की खपत की कीमतों पर असर डाल रही हैं। महंगाई को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर'- खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नकारात्मक डिफ्लेटर - ने असली महंगाई को कम करके दिखाया है। आम नज़रिए से, बताई गई तेज़ आर्थिक विकास दर असलियत में ज़्यादा गणितीय लग सकती है।

देश की वास्तविक जीडीपी विकास दर दुनिया के रूझान के बिल्कुल उलट है। ओईसीडी ग्लोबल इकानॉमिक आउटलुक के विस्तृत अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, दुनिया की आर्थिक विकास दर 2026 में धीमी होकर अनुमानित 2.6 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत हो रही है, जो पिछले सालों की तुलना में कम है। यह सुस्ती मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, क्षेत्रीय आपूर्ति में रुकावट, कम निवेश और बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों के कारण है। ये कारक आम तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहे हैं। इस साल दुनिया की आर्थिक विकास दर पर मुख्य दबाव ऊर्जा के झटकों, बढ़ते व्यापार अवरोधों और ज़्यादा कर्ज़ और उधार का है। भू-राजनीतिक संघर्षों ने, खासकर पश्चिम एशिया में, ईंधन और गैस की आपूर्ति को कम कर दिया है, जिससे सभी स्तरों पर उत्पादन और खपत की लागत बढ़ गई है और महंगाई को बढ़ावा मिला है। एकतरफा टैरिफ उपायों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बिखराव ने सामान के व्यापार की मात्रा के अनुमानों को कम कर दिया है। उधार लेने की ज़्यादा लागत राजकोषीय गुंजाइश को सीमित कर रही है, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, मार्च 2026 के आखिर में भारत का कुल विदेशी कर्ज़ 762.8 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 26.3 अरब ज़्यादा है। इससे कर्ज़-जीडीपी अनुपात 20.8 प्रतिशत हो गया, जो कुल विदेशी देनदारियों में बढ़ोतरी को दिखाता है।

ऊंची ब्याज दरों और व्यापार में बदलावों की वजह से अमेरिकी जीडीपी की विकास दर धीमी होकर लगभग 1.5-2.0 प्रतिशत रह गई है। ऊर्जा पर ज़्यादा निर्भरता और स्थानीय औद्योगिक रुकावटों के कारण यूरो क्षेत्र की आर्थिक विकास दर 0.5 से 1.3 प्रतिशत के आसपास सुस्त बनी हुई है। घरेलू संरचनात्मक बदलावों के बीच चीन की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी होकर लगभग 4.5-4.6 प्रतिशत हो गई है। मौजूदा साल में, दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाएं -अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूके - 2.5 प्रतिशत से कम की बहुत धीमी रफ़्तार से आगे बढ़ रही हैं, जबकि छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत की मज़बूत वास्तविक जीडीपी दर दिखा रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी को 81.36 लाख करोड़ आंका, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 75.46 लाख करोड़ था। इससे 7.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर मिली, जो रिज़र्व बैंक के 2026-27 के लिए 6.7 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है।

> **स्वतंत्र विश्लेषक और आलोचक बताते हैं कि आधार वर्ष बदलने, पुराने डेटा में संशोधन करने और पुराने आंकड़ों को नए इंडेक्स तरीकों के साथ मिलाने से साल-दर-साल प्रतिशत के नतीजों में बढ़ोतरी दिख सकती है। कुछ वैकल्पिक व्याख्याओं का तर्क है कि अगर पुराने या बेमेल आधार समायोजन को हटा दिया जाए, तो कुछ खास सब-सेगमेंट में वास्तविक विकास दर कम दिखती है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि सेवा और हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र उत्साहजनक रफ़्तार दिखा रहे हैं।**

स्वतंत्र विश्लेषक और आलोचक बताते हैं कि आधार वर्ष बदलने, पुराने डेटा में संशोधन करने और पुराने आंकड़ों को नए इंडेक्स तरीकों के साथ मिलाने से साल-दर-साल प्रतिशत के नतीजों में बढ़ोतरी दिख सकती है। कुछ वैकल्पिक व्याख्याओं का तर्क है कि अगर पुराने या बेमेल आधार समायोजन को हटा दिया जाए, तो कुछ खास सब-सेगमेंट में वास्तविक विकास दर कम दिखती है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि सेवा और हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र उत्साहजनक रफ़्तार दिखा रहे हैं, जबकि प्राथमिक कृषि और ग्रामीण सेक्टर अपेक्षाकृत सुस्त बने हुए हैं (तीन प्रतिशत से कम की विकास दर के साथ)। वास्तविक रूप में सकल जमा पूंजी के निर्माण में 11.9 प्रतिशत की तेज़ी आई, जो तेज़ी से क्षमता बढ़ाने, निजी पूंजीगत व्यय और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर लगातार खर्च का संकेत है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसमें बिजली और परिवहन उपकरण के क्षेत्र में हुई भारी बढ़त का अहम योगदान रहा। तृतीयक सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसमें वित्तीय, जमीन जायदाद, आईटी और पेशेवर सेवाओं (जो 12.1 प्रतिशत की दर से बढ़ीं) की बड़ी भूमिका रही। निजी अंतिम उपभोग खर्च में 7.1 प्रतिशत की स्थिर वास्तविक वृद्धि बनी रही, जिससे घरेलू बाजार बाहरी वैश्विक चुनौतियों के असर से बचा रहा।

भारत ने अपने जीडीपी के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। इसके साथ ही, जीएसटी, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और अनिगमित क्षेत्र के उद्यम के सालाना सर्वेक्षण जैसे आधुनिक आंकड़ा स्रोतों को शामिल किया गया है और 'डबल डिफ्लेशन' की पद्धति अपनाई गई है।

इन बड़े बदलावों का मकसद तेज़ी से डिजिटल और औपचारिक हो रही अर्थव्यवस्था को समझना है, हालांकि जब तक पुरानी श्रृंखला के आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक पुराने आंकड़ों से तुलना करना मुश्किल होगा। आंकड़ा श्रृंखला में बदलाव के मुख्य कारणों में आधार वर्ष बदलना, नया आंकड़ा शामिल करना और तरीकों में सुधार करना शामिल है। आधार वर्ष को 2022-23 करने से अर्थव्यवस्था में हाल के संरचनात्मक बदलाव, खपत में बदलाव और कीमतों के सापेक्ष महत्व का पता चलता है। हाई-फ्रीक्वेंसी और बारीक डेटासेट को शामिल करने में जीएसटी रिटर्न, अनिगमित क्षेत्र सर्वेक्षण, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और ई-वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें शामिल हैं। तरीकों में सुधार के लिए आपूर्ति और उपयोग तालिका फ्रेमवर्क, तिमाही आंकड़ों के लिए आनुपातिक डेंटन बेंचमार्किंग और इनपुट लागत को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और कृषि में डबल डिफ़्लेशन जैसे तरीके अपनाए गए हैं। इन सबके कारण पुराने और अप्रचलित तरीकों के बजाय सीधे सर्वे डेटा के ज़रिए अनौपचारिक और डिजिटल/गिग अर्थव्यवस्था के हिस्सों को बेहतर ढंग से दिखाया जा सका है। जब तक आधिकारिक पुराने आंकड़े की नयी श्रृंखला प्रकाशित नहीं हो जाती, तब तक सीधी तुलना नहीं की जा सकती।

फिर भी, यह सोचना गलत है कि 2026 में भारत के आयात और निर्यात पर वैश्विक व्यापार और आर्थिक चुनौतियों का बहुत कम असर पड़ेगा। वैश्विक चुनौतियां—जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष, शिपिंग रूट में रुकावट, माल ढुलाई और ऊर्जा की बढ़ती लागत, और टैरिफ़ नीतियों में बदलाव—भारत के बाहरी क्षेत्र पर दबाव डाल रही हैं, व्यापार घाटे को बढ़ा रही हैं और प्रमुख क्षेत्र में निर्यात की विकास दर को रोक रही हैं। घरेलू खपत बढ़ने और आयात बिल में भारी बढ़ोतरी के कारण देश का वस्तु व्यापार घाटा बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और ज़रूरी शिपिंग रूट के आसपास सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण माल ढुलाई की दरें, बीमा खर्च और ऊर्जा आयात की लागत बढ़ गई है। कृषि, टेक्सटाइल और रत्न व आभूषण जैसे पारंपरिक श्रम-प्रधान निर्यात सेक्टर में पश्चिमी देशों से कम मांग, सुरक्षात्मक टैरिफ़ में बदलाव और व्यापारिक तनाव के कारण साफ़ तौर पर सुस्ती देखी जा रही है। रुपये के कमज़ोर होने और अमेरिका के अलावा अन्य बाज़ारों में विविधता लाने की रणनीतियों के कारण वस्तुओं और सेवाओं के संयुक्त निर्यात में समय-समय पर सुधार देखा गया है। फिर भी, पूरे साल जीडीपी विकास दर को पहली तिमाही के ऊंचे स्तर पर बनाए रखना बहुत मुश्किल लग रहा है।

आपके पत्र

हादसों के शिकार पढ़ने वाले बच्चे ही क्यों?

दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं यह उन लाखों सपनों की राजधानी भी है, जिन्हें लेकर देश के कोने-कोने से बच्चे, युवा और उनके परिवार यहां आते हैं। कोई आईएएस बनने का सपना लेकर आता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने का। कोई छोटे से गांव से चलकर दिल्ली की किसी कोचिंग की सीढ़ियां चढ़ता है और कोई अपने माता-पिता की वर्षों की बचत लेकर एक छोटे-से कमरे में अपना भविष्य खोजता है। लेकिन विडंबना देखिए,जिस दिल्ली में ये बच्चे भविष्य बनाने आते हैं, वही दिल्ली बार-बार उनके वर्तमान को छीन लेती है।

सवाल अब केवल यह नहीं है कि दिल्ली में हादसे क्यों होते हैं। असली सवाल यह है कि बार-बार वही हादसे क्यों होते हैं और हर हादसे के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं जागती? कुव्यवस्था की भयावह तस्वीर हाल की सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना ने फिर सामने रख दी। छात्र-आवास वाली बहुमंजिला इमारत ढहने से सात लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट सामने आई और अधिकांश पीड़ित विद्यार्थियों के होने से छात्र आवासों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न उठे।

सबसे पीड़ादायक बात यह है कि विद्यार्थी दिल्ली में केवल पढ़ाई की फीस नहीं देते। वे कमरा किराये पर लेते हैं, भोजन के लिए भुगतान करते हैं, परिवहन का खर्च उठाते हैं और अपने परिवारों की आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक कीमत पर अपने सपनों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो क्या उन्हें बदले में केवल असुरक्षित कमरे मिलेंगे? क्या उनके लिए अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा, आपातकालीन निकास और स्वच्छ जलनिकासी जैसी सुविधाएं विलासिता हैं?

राजधानी में पढ़ने वाले विद्यार्थी नागरिक नहीं हैं क्या? दिल्ली की प्रशासनिक समस्या का एक और गंभीर पहलू है जिम्मेदारी का बिखराव। नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन विभाग, विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन कई संस्थाएं अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। लेकिन जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी अक्सर किसी एक छोटे कर्मचारी या किसी संचालक पर जाकर रुक जाती है।

हाल की प्रशासनिक जांचों के संबंध में रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि कई त्रासदियों में प्रणालीगत खामियां और प्रशासनिक लापरवाही चिन्हित हुईं, जबकि कार्रवाई अक्सर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रही। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। यदि किसी इमारत को वर्षों तक नियमों के विरुद्ध चलने दिया गया, तो केवल चौकीदार या कनिष्ठ कर्मचारी दोषी कैसे हो सकता है?

लेकिन प्रश्न फिर वही है—यदि इतनी बड़ी संख्या में संस्थान नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो हादसे से पहले प्रशासन कहां था?

-संजीव ठाकुर

ललित सुरजन की कलम से

भाषण और आंकड़ों से परे

'छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने पंचायत शिक्षकों का संविलियन कर शिक्षकों का स्थायी कैडर निर्मित करने का फैसला लिया है। कुछ ऐसा ही फैसला मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लिया है। मेरा शुरू से मानना रहा है कि जब तक स्कूलों में पूर्णकालीन और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होंगे तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। वर्ल्ड बैंक के इशारे पर स्थायी शिक्षकों का कैडर धीरे-धीरे कर पूरे देश में समाप्त कर दिया गया। इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिला। आज अगर वह स्थिति बदलती है तो स्वागत योग्य है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बारे में एक समन्वित दीर्घकालीन नीति बनाकर लागू करना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी विसंगतियां व्याप्त हैं। उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ-साथ शाला भवन, उपकरण, पुस्तकालय, खेल का मैदान, इन सब पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। दिल्ली का मॉडल यहां शायद काम आ सकता है!'

(देशबन्धु में 05 जुलाई 2018 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2017/08/blog-post_9.html

आज पोला अमावस्या

अन्नदाता और उसके सहचर बैलों के सम्मान का पर्व

भाद्रपद अमावस्या भारतीय धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवसर पर स्नान, दान, पितरों का स्मरण और तर्पण जैसे धार्मिक कर्म किए जाते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में इस अमावस्या के अलग नाम और अलग लोकाचार दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में इसी अमावस्या का लोकजीवन से जुड़ा रूप पोला के रूप में सामने आता है। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि एक ही तिथि धार्मिक आस्था, कृषि जीवन और लोकसंस्कृति के अनेक रंगों को अपने भीतर समेट लेती है।

भाद्रपद अमावस्या पर जीवंत होती है छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति। छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसकी हरियाली, नदियों, जंगलों और खनिज संपदा से नहीं है, बल्कि उसकी समृद्ध लोकपरंपराओं और तीज-त्योहारों से भी है। यहां के पर्व प्रकृति, कृषि, पशुधन और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध को अभिव्यक्त करते हैं। इन्हीं लोकपर्वों में पोला अथवा पोरा तिहार का विशेष स्थान है। भाद्रपद अमावस्या के अवसर पर मनाया जाने वाला यह पर्व मूलत: किसान और उसके सबसे विश्वसनीय कृषि-सहचर बैल के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता का पर्व है।

आज खेती के तौर-तरीके बदल रहे हैं। ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरणों ने बैलों पर निर्भरता काफी कम कर दी है। शहरों में रहने वाली नई पीढ़ी के लिए बैल अब कृषि जीवन के प्रत्यक्ष सहभागी के बजाय स्मृति और लोकसंस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन इससे पोला का महत्व समाप्त नहीं होता। बल्कि आज इस पर्व का संदेश और अधिक व्यापक हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अकेले विकास नहीं कर सकता। उसके जीवन और सभ्यता के निर्माण में प्रकृति, पशु-पक्षियों और असंख्य जीवों का योगदान रहा है।

पोला पर्व का संबंध केवल बैलों से ही नहीं, बल्कि खेती और फसल से भी है। लोकमान्यता है कि इसी समय धान की बालियों में दूध भरना प्रारंभ होता है और अन्नमाता गर्भ धारण करती हैं। किसान के लिए यह आने वाली फसल और समृद्धि की आशा का अवसर होता है। इसलिए पोला वास्तव में प्रकृति, कृषि, पशुधन और किसान इन चारों के बीच स्थापित उस जीवनचक्र का उत्सव है, जिसके आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सदियों से आगे बढ़ती रही है।

पोला की सबसे सुंदर विशेषताओं में बच्चों की भागीदारी भी है। ग्रामीण अंचलों में मिट्टी अथवा लकड़ी से बने छोटे-छोटे बैल, चूल्हा, चक्की, चुकिया और अन्य खिलौने तैयार किए जाते हैं। बच्चे उन्हें सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह परंपरा केवल मनोरंजन नहीं है। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को बचपन से ही यह सीख मिलती है कि पशु हमारे जीवन और कृषि व्यवस्था के महत्वपूर्ण साथी हैं। लोकपर्व इस प्रकार बिना किसी औपचारिक पाठशाला के बच्चों को अपनी मिट्टी, संस्कृति और परंपरा का पाठ पढ़ाता है।

पोला केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि पारिवारिक उल्लास और सामुदायिक मेल-मिलाप का अवसर भी है। घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी खान-पान की समृद्ध परंपरा के अनुरूप ठेठरी, खुरमी सहित अनेक व्यंजन इस अवसर पर तैयार किए जाते हैं। बहन-बेटियों के मायके आने, परिवार के साथ समय बिताने और रिश्तों में स्नेह बढ़ाने की परंपरा भी इस पर्व को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है।

-सुरेश सिंह बैस 'शाश्वत'

सार-समाचार

फुटबॉल टुर्नामेंट का फाइनल मुकाबला यंग ब्रदर्स क्लब ने शानदार जीत दर्ज की

आष्टा, देशबन्धु। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के तत्वाधान में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मऊ यूनाइटेड व यंग ब्रदर आष्टा के मध्य खेला गया, जिसमें शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए यंग ब्रदर्स क्लब ने मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। फाईनल मुकाबले में मुख्य अतिथि रूप में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा, योगेंद्र ठाकुर, हरेन्द्र सिंह ठाकुर, डॉक्टर हसीब, डॉ सलीम, परमानंद , शेख आरिफ और साथ में एसआरके सोल्जर की पूरी टीम भी मौजूद रही। इस अवसर पर टूर्नामेंट अध्यक्ष विशाल अटरिया, टूर्नामेंट कमिश्नर उमेर लाला, दानिश, सलमान, फ़हीम, उमेर लाला, कुशलपाल लाला आदि उपस्थित रहे।

पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव ने योजनाओं की जानी जमीनी हकीकत

रायसेन, देशबन्धु। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव डॉ सुदामा पंढरीनाथ खाडे द्वारा बुधवार को रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में भ्रमण कर विभागीय योजनाओं और सेवाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पशु चिकित्सालय औबेदुल्लागंज, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र औबेदुल्लागंज और दुग्ध सहकारी समिति ग्राम आशापुरी का निरीक्षण करते हुए उपलब्ध सुविधाओं, पशु उपचार व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति, दुग्ध संकलन तथा पशुपालकों को मिल रही सेवाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संचालक डॉ पीएस पटेल, उप संचालक डॉ एसके कपूर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमुख सचिव डॉ सुदामा खाडे द्वारा पशु चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान ओपीडी, औषधि भंडार, उपचार कक्ष एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पशुओं के उपचार, टीकाकरण, संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि पशुपालकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तथा आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके उपरांत प्रमुख सचिव द्वारा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाने से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और पशुपालकों की आय में भी सुधार आएगा। उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालकों से संतुलित पशु आहार, बेहतर पशु प्रबंधन, नियमित स्वास्थ्य जांच तथा वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों के प्रति जागरूक करने संबंधी चर्चा की।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप चुनाव को लेकर शस्त्र लायसेंस निलंबित

रायसेन, देशबन्धु। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अगस्त 2026 को जारी आदेशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2026(पूर्वार्द्ध) का कार्यक्रम घोषित किए जाने के फलस्वरूप रायसेन जिले के विकासखण्ड सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, बाड़ी एवं औबेदुल्लागंज अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य पद/जनपद पंचायत सदस्य पद/सरपंच पद एवं पंच के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन-2026 (पूर्वार्द्ध) सम्पादित किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा उप निर्वाचन-2026 (पूर्वार्द्ध) के दृष्टिगत निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस उप निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

जारी आदेश के तहत उप निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत 05 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस आयुध नियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के अंतर्गत उप निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। संबंधित क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को आदेशित किया गया है कि आदेश जारी होने की दिनांक से 03 दिवस के भीतर अपने-अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन में जमा करना सुनिश्चित करें। उक्त निलंबन आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील माना जाएगा।

सांदीपनि विद्यालय के चार विद्यार्थियों का एम.बी.बी.एस. में हुआ चयन

आष्टा, देशबन्धु। नगर के सांदीपनि सी.एम. राइज़ शासकीय उमावि के चार विद्यार्थियों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में सफलता प्राप्त कर एम.बी.बी.एस. के लिए चयनित हुए। नकुल प्रजापति ने शासकीय मेडिकल कॉलेज गजराराजा ग्वालियर, अनुष्का वर्मा ने शासकीय मेडिकल कॉलेज श्योपुर, दामिनी झाला ने महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेंज़ एवं रिसर्च भोपाल और आयुषी धनवाल ने मानसरोवर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सीहोर में प्रवेश लिया। शासन स्तर पर जो भी सहायता हो सकती है वो आपकों प्रदान की जाएंगी। सांदीपनि विद्यालय के प्राचार्य सितवत खान ने बताया कि किसी भी शासकीय विद्यालय से चार विद्यार्थियों का एम.बी.बी.एस. में चयन होना बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम करते हुए नीट की परीक्षा पास करी है। प्राचार्य ने बताया कि इसी विद्यालय के विद्यार्थी में उरूजअली खान शासकीय गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और कपिल, तनिष चौरसिया, आलोक राय व अवनी जैन पूर्व से ही एम.बी.बी.एस. में अध्ययनरत है। शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का एम.बी.बी.एस. में चयन केवल व्यक्तिगत

उपलब्धि ही नही है, बल्कि गौरव की बात है। इससे पता चलता है, कि सीमित संसाधनों के बावजूद परिश्रमी विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कर सकते है। प्राचार्य ने बताया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देकर नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। अभी नीट काउंसलिंग के प्रथम चरण में विद्यालय के चार विद्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस. में हुआ है और आशा है, कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में और भी विद्यार्थी चयनित होंगे।

इन्होंने दी बधाई, जताई खुशी : आयोजित सम्मान समारोह में प्राचार्य सितवत खान, सम्राट ढोके, जितेन्द्र मेवाड़े, पदमा परमार, डॉ. तेजपाल सिंह, वीरेन्द्र सिंह, पवन कुमार राया, सतीश वर्मा सहित चयनित विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यार्थियों के एम.बी.बी.एस. में चयन होने पर एस.डी.एम. महेन्द्र प्रताप सिंह किरार, तहसीलदार रामलाल पगारे, जिला शिक्षा अधिकारी शीलू शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक आर.आर. उईके, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नीलेश सक्सेना, बी.आर.सी.सी अजब सिंह राजपूत, राकेश प्रजापति, अंत्येश धारवां, भूपेन्द्र सिंह, असमा खानम, नेहा अंसारी, सहित जनप्रतिनिधियों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की।

सांची-सलामतपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 3000 लीटर लाहन नष्ट किया, 141 लीटर से अधिक कच्ची व देशी

पारदी मोहल्ले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 आरोपियों पर शिकंजा

सांची, देशबन्धु। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री तथा संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए रायसेन पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सांची एवं सलामतपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक रायसेन आशुतोष गुप्ता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक के मार्गदर्शन में एसडीओपी रायसेन प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बुधवार तड़के ग्राम ज्ञानपुरा गुलगांव के पारदी मोहल्ले में सर्चिंग अभियान चलाया।

पुलिस के अनुसार सुबह करीब 4 बजे की गई कार्रवाई के दौरान अलग-अलग घरों में कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार किया गया करीब 3000 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया गया। वहीं एक महिला के कब्जे से 7 लीटर कच्ची शराब बरामद कर कार्रवाई की गई। सर्चिंग के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई।

कार्रवाई के दौरान सांची पुलिस ने धौल सिंह मोगिया के कब्जे से एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल एवं 55.980 लीटर देशी शराब, निर्मल मोगिया से 5 लीटर, राजा मोगिया से 6 लीटर, पप्पू पिता राधे मोगिया से 5 लीटर तथा गोपाल उर्फ पराग मोगिया से 7 लीटर कच्ची शराब जब्त की। इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

इसी प्रकार सलामतपुर पुलिस ने शेखर मोगिया एवं उमेश मोगिया के कब्जे से एक मोटरसाइकिल तथा देशी शराब, जबकि पप्पू उर्फ प्रकाश एवं अरुण उर्फ अजय मोगिया के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जब्त की। रोकी मोगिया के कब्जे से 22 क्वार्टर तथा राजबाबू मोगिया के कब्जे से 24 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गई।

पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में कुल 141.26 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 68 हजार रुपए तथा तीन मोटरसाइकिलें, जिनकी कीमत करीब दो लाख रुपए है, जब्त की गईं। वहीं कार्रवाई के दौरान 3000 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में कुछ के विरुद्ध पूर्व से मारपीट, वाहन चोरी एवं लूट जैसे अपराध तथा स्थायी वारंट लंबित थे। ऐसे फरार आरोपियों के विरुद्ध भी मौके पर कार्रवाई की गई। 12 आरोपियों पर कार्रवाई 7 3000 लीटर लाहन नष्ट 7 141.26 लीटर शराब जब्त 7 3 मोटरसाइकिलें जब्त 7 करीब 2.68 लाख रुपए की जब्ती की।

शाम ढलते ही नगर की सड़कों पर पुलिस की गश्त, जुआ-सट्टा और अवैध शराब कारोबारियों में बढ़ा खौफ

सांची, देशबन्धु। नगर में अपराध एवं अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सक्रिय है। शाम होते ही पुलिस का फ्लैगमार्च एवं गश्त शुरू हो जाती है, जो देर रात तक नगर के प्रमुख मार्गों, चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में जारी रहता है। रातभर गूंजता है पुलिस वाहन का सायरन नगर में पुलिस की रात्रि गश्त भी तेज कर दी गई है। रात के समय पुलिस वाहनों के सायरन की आवाज नगर में सुनाई देती रहती है। पुलिस द्वारा अनजान एवं संदिग्ध लोगों से पूछताछ के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर निगरानी की जा रही है। रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहे, सार्वजनिक स्थल और सुनसान क्षेत्रों के साथ-साथ रात्रि में श्मशान घाट जैसे स्थानों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। थाना प्रभारी रामविलोचन शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के तहत नगर एवं आसपास के क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार गश्त, फ्लैगमार्च एवं कार्रवाई की जा रही है। जुआ, सट्टा, अवैध शराब सहित अन्य अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर पुलिस की लगातार नजर है।

पुलिस की सतर्कता से अपराधियों पर अंकुश, प्रतिदिन निकल रहा फ्लैगमार्च

यूसीसी कानून के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

आष्टा, देशबन्धु। एआईएमआईएम की यात्रा प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान के नेतृत्व में प्रदेश भर में निकाली जा रही है जो कि बुरहानपुर इंदौर धार से होते हुए आष्टा पहूंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया, तत्पश्चात रैली के रूप में पुराना बसस्टेंड अली चौक से रैली के रूप में पुरानी सब्जी मंडी कसाई चौराहा सिकंदर बाजार सुभाष चौक होते हुए तहसील कार्यालय पहूंचे जहां मोहसिन अली खान ने एसडीएम महेन्द्र कुमार किरार को महामहीम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने किया उन्होने ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि यूसीसी कानून मुस्लिम विरोधी है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एआईएमआईएम उसका विरोध करती है। इसके बाद रात्रि 9 बजे अली चौक पर एक आमसभा भी आयोजित की गई जिसमें प्रमुख रूप से शेख आरिफ, बाबर, बाकिर मुल्लाजी, बुरहान, जामिन, अदनान जावर, साकिब, रिजवान, रियाज, तोहीद, फैजान, उपस्थित रहे।

कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों के दल ने खेतों में पहुंचकर सोयाबीन फसल का लिया जायजा

किसानों से चर्चा कर कीट और रोगों से बचाव संबंधी उपायों की दी जानकारी

रायसेन, देशबन्धु। जिले में कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण पीला मोजेक रोग और सोयाबीन की तने में तना मक्खी के कारण पौधे धीरे-धीरे पीले होकर सूखने की जानकारी मिलने पर इससे बचाव हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों के साथ निगरानी दल गठित किए गए हैं। जिनके द्वारा खेतों का भ्रमण कर फसलों में कीट-व्याधि के प्रकोप का निरीक्षण, नियंत्रण और कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है इसी क्रम में गत दिवस गैरतगंज विकासखण्ड के ग्राम सहजपुर, आलमपुर व पापड़ा आदि में गत दिवस किसानों के खेत पर जाकर उपसंचालक कृषि श्री केपी भगत, वैज्ञानिक डॉ प्रदीप कुमार द्विवेदी, सहायक संचालक कृषि केके ठाकुर, डॉ गोविन्द नामदेव वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गैरतगंज, अरूण अहिरवार कृषि विस्तार अधिकारी गैरतगंज में फसलों का निरीक्षण कर कृषकों चंद्रेष राजपूत, नीरज राजपूत, चैन सिंह यादव, रिजबान अहमद एवं अन्य किसानो के साथ चर्चा की गई और रोगों से बचाव हेतु सलाह दी गई।

उप निरीक्षक से निरीक्षक बनीं पूजा सिंह

पुलिस कप्तान ने लगाया तीसरा सितारा

भैरूंदा, देशबन्धु। पुलिस विभाग में पदोन्नति के बाद थाना सब इंस्पेक्टर पूजा सिंह राजपूत को तीसरा स्टार मिलने पर भैरूंदा थाने में सम्मान किया गया। पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे की उपस्थिति में पूजा सिंह राजपूत को दो स्टार से पदोन्नत होकर तीसरा स्टार लगाया गया। गौरतलब है कि पूजा सिंह राजपूत इससे पहले भी एक बार भैरूंदा थाने में पदस्थ रह चुकी हैं। अपने सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और बेहतर पुलिसिंग के कारण उन्होंने नगरवासियों के बीच विशेष पहचान बनाई है। यही कारण है कि उनके पदोन्नत होकर तीसरा स्टार मिलने पर थाना स्टाफ के साथ-साथ नगरवासियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत कर नई जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दीं।

सेमनरी रोड फीडर मरम्मत के चलते तीन घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बंद

आष्टा, देशबन्धु। 33/11 केवी सेमनरी सब स्टेशन से जुड़े 11 केवी सेमनरी रोड फीडर में आवश्यक विद्युत रखरखाव कार्य के चलते गुरुवार, 10 सितंबर 2026 को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक करीब तीन घंटे बिजली सप्लाई बंद रखी जाएगी। विभाग के अनुसार 11 केवी सेमनरी रोड फीडर पर आवश्यक मेंटेनेंस एवं विद्युत कार्य के लिए यह शटडाउन लिया जा रहा है। इस दौरान फीडर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों एवं कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत आपूर्ति बाधित रहने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सेमनरी सब स्टेशन के आसपास का क्षेत्र, आदर्श कॉलोनी, अंजनी नगर, पुष्प हॉस्पिटल क्षेत्र, मॉडर्न स्कूल के पास का इलाका, देवेंद्र परमार कॉलोनी तथा घनश्यामपुरा रोड से लगे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के दौरान बिजली उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

ग्राम गुदावल में कलश वंदन यात्रा में शामिल हुए विधायक श्री पटवा

रायसेन, देशबन्धु। संत शिरोमणि रविदासजी की 650वीं जन्म जयंती वर्ष पर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए "श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं रथ यात्रा" के तहत कलश वंदन यात्रा जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुंच रही है। बुधवार को कलश वंदन यात्रा गुदावल पहुंची, यहां भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत श्री गुरु रविदासजी महाराज का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान एवं समान अवसर प्राप्त हों। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और विकास के लिए समान रूप से योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यह सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कलश वंदन यात्रा के माध्यम से संत रविदासजी के सामाजिक समरसता, समानता, बंधुत्व और मानव कल्याण का संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

पन्यास प्रवर यशोजीत विजय महाराज बोले

धर्म को समझ लिया तो वही मोक्ष तक ले जाएगा

आष्टा, देशबन्धु। पर्यूषण महापर्व के दूसरे दिन तीर्थ नेमिनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर किला के उपाश्रय में पन्यास प्रवर यशोजीत विजय महाराज ने आशीष वचन देते हुए कहा कि प्रवचन केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए सुनना और समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म आराधना अवश्य करना चाहिए। धर्म को समझ लिया जाए तो यही धर्म व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है। पन्यास प्रवर ने कहा कि व्यक्ति को यह सोचकर उपवास करना मेरा सौभाग्य है और पारणा करना मेरा विभाव है। व्यक्ति अनंत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है और आज मनुष्य संस्कारित नहीं बन पा रहा है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे भी स्वाध्याय में लगा ले तो वह साधना दीक्षा के समान फलदायी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि आज व्यक्ति धर्म, त्याग और तपस्या नहीं कर सकता तो फिर कब करेगा। मन में दीक्षा का भाव नहीं आएगा तो व्यक्ति संसार में ही भटकता रहेगा। यशोजीत विजय महाराज ने कहा कि अट्ठम और दीक्षा जैसे तप व्यक्ति को संस्कारित बनाते हैं। कर्मों को काटने वाला जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही सही अर्थों में दीक्षा की ओर ले जाता है।

बाला गांव में स्वधार मेले का आयोजन, ग्रामीणों को दी डिजिटल सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी

भैरूंदा, देशबन्धु। *ग्राम बाला गांव में स्वधार फिन एक्सेस एवं बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में स्वधार मेले का आयोजन किया गया। मेले में ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा तथा केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।*

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को फर्जी कॉल, मैसेज और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। साथ ही डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, केवाईसी प्रक्रिया और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से

अवगत कराया गया।

मेले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अटल पेंशन योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान कई ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पंजीयन कर योजनाओं का लाभ भी प्राप्त किया।

कार्यक्रम में स्वधार फिन एक्सेस की ओर से बबली शर्मा तथा बैंक ऑफ इंडिया, बाला गांव के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) जितेंद्र गोस्वामी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मेले में भाग लेकर डिजिटल सुरक्षा, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

सार समाचार

संत रविदास की प्रतिमा स्थापना समारोह आज

रायसेन,देशबन्धु। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की पावन स्मृति और उनके समतामूलक विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रायसेन में 10 सितंबर को प्रतिमा स्थापना समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम गुरुवार सुबह 10: 30 बजे कलईपुरा वार्ड नंबर-17 स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में होगा। भोपाल रोड पर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में जयपुर से लाई गई करीब 3.5 फीट ऊंची संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा स्थापना भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी की ओर से कराई जा रही है। प्रतिमा स्थापना समारोह के दौरान समरसता भोज का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य संत रविदास जी के समानता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव के संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर श्रीराम परिसर में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह की व्यवस्थाओं और अलग-अलग जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हुई। मौजूद लोगों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सहभागिता का संकल्प लिया। डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी सामाजिक समरसता और समाज को जोड़ने के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि समरसता केवल विचार नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में उतारने का संकल्प है।

जयपुर से लाई 3.5 फीट ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित

रायसेन-२

मिश्र तालाब पर जीत किसी की नहीं, रायसेन की होनी चाहिए: मिश्र

रायसेन,देशबन्धु। मिश्र तालाब नगर की धरोहर है और इसके कायाकल्प को किसी संस्था के बीच श्रेय की प्रतिस्पर्धा नहीं बनाया जाना चाहिए। यह रायसेन के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय है। समिति और नगर पालिका परिषद यदि कदम से कदम मिलाकर काम करें तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावी होंगे।

यह बात रायसेन जिला विकास समिति के अध्यक्ष हरीश मिश्र 'वृक्ष मित्र' ने कही। उन्होंने कहा कि मिश्र तालाब के कायाकल्प की दिशा में समिति ने एक कदम रखा है और नगर पालिका परिषद ने दूसरा। दोनों पहल स्वागत योग्य हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें प्रतिस्पर्धा के बजाय साझेदारी में बदला जाए।

मिश्र ने कहा कि पिछले वर्ष समिति द्वारा चलाए गए 'कदम-कदम पर कदंब' अभियान में लगाए गए कदंब पौधों को नगर पालिका परिषद ने सालभर पानी उपलब्ध कराया। यह पालिका की जिम्मेदारी थी, लेकिन अभियान के प्रति सहयोग की सराहनीय मिसाल भी रही। इसी भावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

समिति के संयोजक दीपक लोधी ने कहा कि 'कदम-कदम पर कदंब' और 'सरोवर हमारे—धरोहर हमारी' जैसे अभियान किसी एक संस्था के नहीं हैं। इनमें नगर के नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। समिति और नगर पालिका परिषद की संयुक्त बैठक आयोजित कर स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें जिम्मेदारियां और समय-सीमा तय हों।

जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे नौनिहाल, हादसे का खतरा

नरोदा में किराए के कमरों में लग रही कक्षाएं, उकायला स्कूल का प्लास्टर गिरा, फर्श उखड़ा;

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

गंजबासौदा, देशबन्धु। क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढने वाले नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई स्कूल भवनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहां ब'चों की कक्षाएं लगाना जोखिम भरा बना हुआ है। ग्राम नरोदा में स्कूल भवन जर्जर होने के कारण कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई दो अलग-अलग किराए के कमरों में कराई जा रही है। वहीं ग्राम उकायला के सरकारी स्कूल भवन का प्लास्टर लगातार गिर रहा है और फर्श पूरी तरह उखड़ चुका है। स्कूल के शौचालय भी बदहाल स्थिति में हैं। सरकारी स्कूलों की इस बदहाल स्थिति को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार दोपहर कलेक्टर के नाम तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। यह कार्रवाई युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे 'स्कूल बचाओ अभियानज् के तहत स्कूलों के निरीक्षण के बाद की गई है।

बाक्स-नरोदा में भवन नहीं, किराए के कमरों में पढ़ाई

ग्राम नरोदा के सरकारी स्कूल भवन की स्थिति बेहद खराब बताई गई है। भवन जर्जर होने के कारण ब'चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं किराए के दो अलग-अलग कमरों में संचालित की जा रही हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को इसी व्यवस्था के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यार्थियों के भविष्य और सुरक्षा को देखते हुए नरोदा में नए स्कूल भवन को तत्काल स्वीकृति दी जाए।

उकायला में गिर रहा प्लास्टर, फर्श भी उखड़ा

ग्राम उकायला के सरकारी स्कूल भवन की हालत भी चिंता बढ़ाने वाली है। निरीक्षण के दौरान भवन का प्लास्टर जगह-

जगह से गिरने और फर्श के पूरी तरह उखड़ जाने की बात सामने आई। स्कूल के शौचालयों की स्थिति भी खराब है। ऐसे में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। कांग्रेस ने स्कूल भवन का तत्काल तकनीकी निरीक्षण कराकर आवश्यक मरम्मत कार्य को मंजूरी देने की मांग की है।

कभी भी हो सकता है हादसा

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जर्जर स्कूल भवनों में ब'चों की कक्षाएं संचालित होना गंभीर चिंता का विषय है। भवनों की स्थिति को देखते हुए कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि ब'चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्थायी समाधान करना चाहिए। ज्ञापन में सुरक्षित पेयजल, उपयोग योग्य शौचालय और ब'चों के लिए सुरक्षित अध्ययन स्थल उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है।

कांग्रेस ने कहा कि जब तक स्कूल भवनों का निर्माण या मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, तब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए।

मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन

नगर कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो नगर कांग्रेस और युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ब'चों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार में सरकारी विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। कई स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हैं और विद्यार्थी किराए के भवनों में पढने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर भवनों की स्थिति कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसी गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की गई है।

बलात्कार के प्रकरण में 2 हजार रुपए का इनामी फरार आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस की लगातार दबिश और सक्रिय मुखबिर तंत्र से मिली सफलता

विदिशा, देशबन्धु। पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने बलात्कार के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे 2,000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

प्रकरण का विवरण

दिनांक 16 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली, जिला विदिशा में अपराध क्रमांक 952/2026, धारा 70(1), 115(2), 351(3), 69 बी.एन.एस. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी आशीष तिवारी पिता राजेंद्र तिवारी, उम्र 27 वर्ष, निवासी नगतला राजपूत कॉलोनी, विदिशा लगातार फरार चल रहा था। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 2,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

लगातार प्रयासों के बाद आरोपी गिरफ्तार

फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार

सराहनीय भूमिका

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी आनंद राज, उप निरीक्षक रणवीर सिंह, प्रधान आरक्षक विजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र शर्मा, आरक्षक आशीष रावत, आरक्षक अनिदेश सेंगर एवं आरक्षक शिशुपाल सिंह दांगी की सराहनीय भूमिका रही

संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। इसी दौरान प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए इनामी फरार आरोपी आशीष तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है

सिरोंज विकासखंड की 27 गौशालाओं को 8.29 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी

सिरोंज,देशबन्धु। निराश्रित और बेसहारा गौवंश के भरण-पोषण एवं बेहतर देखभाल के लिए शासन द्वारा सिरोंज विकासखंड की शासकीय और अशासकीय गौशालाओं को 8 करोड़ 29 लाख 75 हजार 730 रुपये की राशि जारी की गई है। गौ संवर्धन बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजीयन प्रारंभ होने से मार्च 2026 तक विकासखंड की 27 गौशालाओं को यह राशि प्रदान की गई है। इनमें 24 शासकीय और 3 अशासकीय गौशालाएं शामिल हैं। जारी राशि से गौशालाओं में गौवंश के लिए चारा, भूसा, दाना, पानी, शेड सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था और रखरखाव किया जाएगा। इसका उद्देश्य बेसहारा गौवंश को पर्याप्त आहार उपलब्ध कराने के साथ उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है। शासकीय गौशालाओं में ग्राम पंचायत छापू की स्वामी विवेकानंद गौशाला को 28 लाख 92 हजार 720 रुपये, खोदूपुर की श्री कामधेनु गौशाला को 9 लाख 92 हजार 240 रुपये, कांजीखेड़ी की गोपाल गौशाला को 1 करोड़ 20 लाख 79 हजार 320 रुपये, अनूपपुर की ग्राम पंचायत गौशाला को 51 लाख 6 हजार 180 रुपये, गोपाल नगर की श्री विष्णु गौशाला को 45 लाख 11 हजार 800 रुपये तथा संतोषपुर की श्री गौशाला समिति को 33 लाख 6 हजार 260 रुपये की राशि जारी हुई है।

इसी प्रकार भौरिया की समोनी गौशाला को 34 लाख 52 हजार 80 रुपये, इमलानी की उषापुरी गौशाला को 27 लाख 9 हजार 760 रुपये, दीकनाखेड़ा की श्री बांके बिहारी गौशाला को 31 लाख 18 हजार 200 रुपये, झंडवा की श्याम गौशाला को 24 लाख 86 हजार 920 रुपये, सोना की श्री राधाकृष्णम शरणम् गौशाला को 28 लाख 20 हजार 740 रुपये, कचनारिया की मोतीलाल गौशाला को 20 लाख 2 हजार 160 रुपये तथा पारधा की राधा रानी गौशाला को 26 लाख 65 हजार 80 रुपये जारी किए गए हैं।प्यासी की श्री सिद्ध बाबा गौशाला को 25 लाख 42 हजार 740 रुपये, धानोदा की स्वर्गीय श्री हुकम सिंह गौशाला को 24 लाख 56 हजार 940 रुपये, परसोरा की गोविंद गौशाला को 20 लाख 33 हजार 360 रुपये, बामोरीशाला की मां जानकी गौशाला को 19 लाख 74 हजार 310 रुपये, रतनबर्री की श्री कृष्ण गौशाला को 25 लाख 66 हजार 740 रुपये, सुल्तानपुर की श्री शिवनंदनी गौशाला को 24 लाख 31 हजार 460 रुपये, पामाखेड़ी की श्री शिवाजी गौशाला को 12 लाख 11 हजार 440 रुपये, देवपुर की श्री बाबा विश्वनाथ गौशाला को 30 लाख 40 हजार 320 रुपये, लिधौड़ा की श्री कृष्ण गौशाला को 28 लाख 48 हजार 80 रुपये, चुनियाखोह की सांवरिया सेठ गौशाला को 54 लाख 23 हजार 560 रुपये तथा भगवंतपुर की शासकीय गौशाला को 3 लाख 44 हजार 480 रुपये की राशि जारी हुई है।

वहीं सिरोंज की तीन अशासकीय गौशालाओं को भी सहायता राशि मिली है। इनमें श्री कृष्ण गौशाला को 46 लाख 86 हजार 80 रुपये, कामधेनु गौशाला को 7 लाख 90 हजार 760 रुपये और श्री दिगंबर जैन गौशाला को 24 लाख 82 हजार रुपये की राशि जारी की गई है।

12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

रायसेन,देशबन्धु। नगर पालिका परिषद रायसेन द्वारा नागरिकों को बकाया संपत्ति कर एवं जलकर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा कर दाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।लोक अदालत के दौरान बकाया संपत्ति कर एवं जलकर की राशि जमा करने वाले करदाताओं को शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा नागरिको से अपील की गयी है की 12 सितंबर 2026 शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने संपत्ति कर एवं जलकर का भुगतान करें। समय पर कर जमा करना न केवल नागरिकों की जिम्मेदारी है, बल्कि इससे नगर के विकास एवं मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी सहयोग मिलता है।

पारदी मोहल्ले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 आरोपियों पर शिकंजा

सांची-सलामतपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 3000 लीटर लाहन नष्ट किया, 141 लीटर से अधिक कच्ची व देशी शराब तथा तीन मोटरसाइकिलें जब्त

सांची, देशबन्धु। अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री तथा संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए रायसेन पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सांची एवं सलामतपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक रायसेन आशुतोष गुप्ता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक नायक के मार्गदर्शन में एसडीओपी रायसेन प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बुधवार तड़के ग्राम ज्ञानपुरा गुलगांव के पारदी मोहल्ले में सर्चिंग अभियान चलाया।

पुलिस के अनुसार सुबह करीब 4 बजे की गई कार्रवाई के दौरान अलग-अलग घरों में कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार किया गया करीब 3000 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया गया। वहीं एक महिला के कब्जे से 7 लीटर कच्ची शराब बरामद कर कार्रवाई की गई। सर्चिंग के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई।

कार्रवाई के दौरान सांची पुलिस ने धौल सिंह मोगिया के कब्जे से एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल एवं 55.980 लीटर देशी शराब, निर्मल मोगिया से 5 लीटर, राजा मोगिया से 6 लीटर, पप्पू पिता राधे मोगिया से 5 लीटर तथा गोपाल उर्फ पराग मोगिया से 7 लीटर कच्ची शराब जब्त की। इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।

इसी प्रकार सलामतपुर पुलिस ने शेखर मोगिया एवं उमेश मोगिया के कब्जे से एक मोटरसाइकिल तथा देशी शराब, जबकि पप्पू उर्फ प्रकाश एवं अरुण उर्फ अजय मोगिया के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जब्त की। रोकी मोगिया के कब्जे से 22 क्वार्टर तथा राजबाबू मोगिया के कब्जे से 24 क्वार्टर देशी शराब बरामद की गई।

पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में कुल 141.26 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 68 हजार रुपए तथा तीन मोटरसाइकिलें, जिनकी कीमत करीब दो लाख रुपए है, जब्त की गईं। वहीं कार्रवाई के दौरान 3000 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया गया।

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में कुछ के विरुद्ध पूर्व से मारपीट, वाहन चोरी एवं लूट जैसे अपराध तथा स्थायी वारंट लंबित थे। ऐसे फरार आरोपियों के विरुद्ध भी मौके पर कार्रवाई की गई।

फरार आरोपियों की धरपकड़ और अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

12 आरोपियों पर कार्रवाई: 7 3000 लीटर लाहन नष्ट 7 141.26 लीटर शराब जब्त 7 3 मोटरसाइकिलें जब्त 7 करीब 2.68 लाख रुपए की जब्ती

बारिश थमी तो खेतों में तेज हुई उड़द की कटाई

कम पैदावार ने किसानों की बढ़ाई चिंता, दो बीघा में 70-80 किलो ही निकल रही उड़द, सोयाबीन में येलो मोजेक का प्रकोप

गंजबासौदा, देशबन्धु। विकासखंड क्षेत्र में बारिश का दौर थमने के बाद अब किसानों ने खेतों में पककर खड़ी उड़द की फसल को समेटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले तीन दिनों से तेज धूप निकलने के बाद खेतों में सुबह से ही कटाई का काम शुरू हो जाता है। किसान परिवार सहित मजदूरों को लगाकर जल्द से जल्द फसल को सुरक्षित करने में जुटे हैं। हालांकि, इस बार उड़द की कम पैदावार किसानों की चिंता बढ़ा रही है। हालात यह हैं कि कई किसानों को फसल से लागत निकलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बारिश के कारण उड़द की फसल को खेत में अधिक समय तक खड़ा रखना किसानों के लिए जोखिम भरा है। धूप निकलते ही किसान पकी फसल की कटाई कर उसे खेतों में ही सुखाने के लिए फैला रहे हैं। अ'छी तरह सूखने के बाद थ्रेसिंग कर दाना अलग किया जाएगा। किसान धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उनके करीब 8 बीघा खेत में उड़द की फसल लगी है। आसपास के गांवों से मजदूर बुलाकर तेजी से कटाई कराई जा रही है, ताकि मौसम दोबारा खराब

होने से पहले फसल को सुरक्षित किया जा सके।

दो बीघा में 70-80 किलो उत्पादन

जिन किसानों ने उड़द की थ्रेसिंग करा ली है, उनकी चिंता और बढ़ गई है। किसानों के अनुसार कई खेतों में उत्पादन बेहद कम निकल रहा है। करीब दो बीघा खेत से महज 70 से 80 किलो उड़द निकलने की स्थिति सामने आ रही है। इतनी कम पैदावार में बीज, खाद, दवा, मजदूरी और अन्य कृषि खर्च निकालना किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है। किसानों का कहना है कि मौसम की मार का असर इस बार फसल के उत्पादन पर साफ दिखाई दे रहा है।

धूप निकलते ही खेतों में बढ़ी हलचल

पिछले तीन दिनों से तेज धूप निकलने के बाद खेतों में कृषि कार्य तेजी से शुरू हो गए हैं। किसान कटाई के साथ कटी हुई फसल को सुखाने में जुटे हैं। खेतों में जगह-जगह उड़द की कटी फसल के ढेर और उसे सुखाने का काम दिखाई दे रहा है। किसानों की कोशिश है कि मौसम साफ रहने के दौरान अधिक से अधिक फसल की कटाई और थ्रेसिंग का काम पूरा कर लिया जाए।

सोयाबीन में येलो मोजेक ने बढ़ाई परेशानी

उड़द के साथ अब सोयाबीन की फसल को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के बाद कई खेतों में येलो मोजेक बीमारी का असर दिखाई देने लगा है। धूप निकलते ही किसान बीमारी से प्रभावित फसल को बचाने के लिए खेतों में दवाओं का छिड?ाव कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक ओर उड़द की कम पैदावार ने परेशान किया है, वहीं सोयाबीन में बीमारी का प्रकोप नई चिंता बन गया है। कृषि विभाग के अधिकारी सूर्यभान सिंह थानेश्वरी ने बताया कि उड़द की फसल की कटाई का समय होने के कारण किसान खेतों में तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं सोयाबीन की फसल में बीमारी से बचाव के लिए किसानों को आवश्यक दवाओं का छिड?ाव करने की सलाह दी जा रही है। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय फसल की कम पैदावार है। किसानों का कहना है कि खेती में लगातार बढ़ती लागत के बीच यदि उत्पादन इतना कम रहा तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब किसानों की निगाहें फसल के भाव और शेष खेतों से होने वाले उत्पादन पर टिकी हैं।

[अर्थ जगत]

सर्वाधिक बढने वाले शेयर

अडानी पोर्ट्स	3.67 प्रतिशत
टाटा स्टील	2.42 प्रतिशत
ट्रेंट	1.12 प्रतिशत
एनटीपीसी	0.53 प्रतिशत
एशियन पेंट्स	0.08 प्रतिशत

सर्वाधिक घटने वाले शेयर

एचसीएल टेक्नो	4.55 प्रतिशत
इंफोसिस	4.43 प्रतिशत
टेक महिंद्रा	3.87 प्रतिशत
टीसीएस	2.26 प्रतिशत
एचडीएफसी बैंक	2.23 प्रतिशत

सर्राफा

सोना (प्रति दस ग्राम)स्टैंडर्ड	1,52,225
बिटुर	88,730
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	39,795
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	2,36,423
वायदा	70,857
चांदी सिक्का लिवाली	900
बिकवाली	880

मुद्रा विनिमय

मुद्रा	क्रय	विक्रय
अमेरिकी डॉलर	95.70	92.64
पौड स्टर्लिंग	129.75	125.11
यूरो	111.68	107.52
चीन युआन	14.96	13.24

अनाज

देसी गेहूँ एमपी	2400-3000
गेहूं दडा	2862.70
आटा	2800-2900
मैदा	2900-2950
चोकर	2000-2100

मोटा आनाज

बाजरा	1300-1305
मक्का	1350-1500
ज्वार	3100-3200
जौ	1430-1440
काबुली चना	3500-4000

शुगर

चीनी एस	5,803
चीनी एम	4500-4600
मिल डिलीवरी	3620-3720
गुड़	5,976

दाल-दलहन

चना	5700-5800
दाल चना	8,004.95
मसूर काली	8231.25
उड़द दाल	11338.35
मूंग दाल	10202.51
अरहर दाल	11449.82

पारादीप में क्षमता विकसित करेगी अडाणी पोर्ट्स

अहमदाबाद, 9 सितम्बर (एजेंसियां)। अडाणी पोर्ट्स ने बुधवार को कहा कि उसे ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर दो ड्राई बल्क बर्थ्स को विकसित और परिचालन करने के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) मिला है। इससे अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) की क्षमता 18 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) बढ़ जाएगी और कुल पोर्टफोलियो का आकार 671 एमएमटीपीए तक पहुंच जाएगा। इससे कंपनी को 2030 तक 1 बिलियन टन कार्गो तक पहुंचने के उसके लक्ष्य में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।

भारत-अमेरिका समझौता अंतिम चरण में : अग्रवाल

वरीयता प्राप्त बाजार पहुंच के ढांचे पर काम जारी

मुंबई, 9 सितम्बर (एजेंसियां)। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि दोनों देश समझौते के अधिकांश हिस्सों पर सहमति बना चुके हैं और अब एक ऐसे ढांचे पर काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों को एक-दूसरे के बाजारों में वरीयता प्राप्त पहुंच (प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस) उपलब्ध करा सके। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है, लेकिन वार्ताएं उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी हैं।

मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के दौरान मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ विषयों पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन समझौते को उचित समय पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। वाणिज्य सचिव ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे भारत और अमेरिका एक-दूसरे को वरीयता प्राप्त बाजार पहुंच प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत मुख्य रूप

‘कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है, लेकिन वार्ताएं उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी हैं : **राजेश अग्रवाल, वाणिज्य सचिव**

से मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) शुल्क व्यवस्था के तहत काम करता है, जबकि अमेरिका वर्तमान में कार्यकारी शुल्क (एक्जीक्यूटिव टैरिफ) प्रणाली का उपयोग कर रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो शुल्कों में अंतर पैदा कर भारतीय और अमेरिकी व्यवसायों को विशेष लाभ प्रदान कर सके।

राजेश अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के कारोबारी समुदायों के बीच संवाद पहले से ही सक्रिय है और उद्योग जगत सरकारों के बीच बनी व्यापक समझ से संतुष्ट दिखाई देता है। उनका मानना है कि समझौता लागू होने के बाद व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिल सकती है।

फिनटेक निर्यात बढ़ाने पर भारत का जोर

यूपीआई व डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल साउथ तक ले जाने की तैयारी

मुंबई। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि भारत को अपनी फिनटेक क्षमताओं, विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के अनुभव का उपयोग करते हुए वैश्विक बाजारों में विस्तार करना चाहिए। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोलते हुए अग्रवाल ने कहा कि भारत के पास विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों में अपनी डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवाओं का विस्तार करने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर फिनटेक सेवाओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और यदि भारत इस व्यापार में केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी भी हासिल कर लेता है, तो देश का फिनटेक सेवा निर्यात मौजूदा 8 अरब डॉलर से बढ़कर 60 से 80 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
राजेश अग्रवाल ने कहा कि फिनटेक सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। यदि हम इसमें 10 प्रतिशत योगदान भी हासिल करते हैं, तो यह 8 अरब डॉलर से 60-80 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुंचने की यात्रा हो सकती है। उन्होंने बताया कि भारत पहले से ही अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल को अन्य देशों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। इस उद्देश्य से भारत ने अब तक लगभग 23 देशों के साथ डीपीआई सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत में मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग में जबरदस्त उछाल

2021 से 49 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (एजेंसियां)। भारत का विनिर्माण क्षेत्र तेजी से विस्तार के दौर से गुजर रहा है और इसका सीधा असर औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार पर दिखाई दे रहा है। वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से भारत में सकल मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग बढ़कर 6.9 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गई है। इस दौरान क्षेत्र ने 49 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है, जो देश में विनिर्माण गतिविधियों के तेजी से विस्तार को दर्शाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और वर्ष 2030 तक औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इस तेजी के साथ विनिर्माण क्षेत्र अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3पीएल) के बाद औद्योगिक परिसंपत्तियों का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है। इसे भारत के औद्योगिक रियल एस्टेट ढांचे में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में सकल अवशोषण 1.92 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच गया था, जबकि 2026 की पहली छमाही में ही यह 1.02 करोड़ वर्ग फुट दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। बढ़ती मांग यह संकेत देती है कि देश में विनिर्माण कंपनियां नए उत्पादन केंद्र और आधुनिक औद्योगिक सुविधाएं तेजी से स्थापित कर रही हैं।

रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग अवशोषण लगभग 4.6 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंच सकता है। यह प्रवृत्ति भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में बढ़ते कदमों और विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप मानी जा रही है।

सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना-चांदी में तेजी

मुंबई, 9 सितम्बर (एजेंसियां)। वैश्विक स्तर पर अस्थिरता से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना और चांदी में बुधवार को तेजी देखी गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोंजिग 1,52,579 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले मामूली कमजोरी के साथ 1,52,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। लेकिन शुरुआती कारोबार में ही इसमें बढ़त देखी गई और यह 11:17 पर 547 रुपए या 0.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,53,126 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

अब तक के कारोबार में सोने ने 1,52,101 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,53,168 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ है, जो

दिखाता है कि सोने का रुझान तेजी की ओर है। सोने के साथ चांदी में भी तेजी देखी जा रही है। चांदी का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोंजिग 2,39,427 रुपए प्रति किलो के मुकाबले मामूली तेजी के साथ 2,39,620 रुपए प्रति किलो पर खुला। खबर लिखे जाने तक यह 1,169 रुपए या 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,40,596 रुपए प्रति किलो पर थी।

एआई के अवसरों के लिए रहे तैयार : मोदी

वडोदरा, 9 सितम्बर (देशबन्धु)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से तेजी से उभर रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अवसरों के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में कौशल, नवाचार और तकनीक के महत्व पर जोर दिया।

‘नमो फॉर विकसित भारत’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को एआई के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे कौशल विकसित करने होंगे, जिन्हें तकनीक और वैश्विक आवश्यकताओं में बदलाव के साथ लगातार उन्नत किया जा सके। एआई कृषि, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और रोबोटिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवसर पैदा करेगा।

प्रधानमंत्री की युवाओं के साथ

■ **एआई कौशल व औद्योगिक हब के रूप में वडोदरा के विकास पर जोर**

यह बातचीत गुजरात के लिए एक बड़े विकास अभियान के साथ हुई, जिसमें उन्होंने वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को और मजबूत करेंगी। इस दौरे का एक प्रमुख आकर्षण 2,800 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा होना रहा।

प्रधानमंत्री ने वडोदरा की शिक्षा और औद्योगिक केंद्र के रूप में रही पहचान से लेकर आधुनिक विनिर्माण और उभरती तकनीकों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हुए विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कपड़ा, टाइल्स, तेल और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्रों में शहर की प्रगति तथा एक बड़े एमएसएमई हब के रूप में इसके विस्तार को रेखांकित किया। उन्होंने भारत की एयरोस्पेस विनिर्माण यात्रा में वडोदरा की भूमिका का भी उल्लेख किया, जिसमें सी-295 विमान कार्यक्रम शामिल है।

बिकवाली के दबाव से लुढ़के शेयर बाजार

■ **सेंसेक्स 1.08 प्रतिशत नीचे 74,764.23 अंक पर रहा**

■ **निफ्टी 0.86 प्रतिशत टूटकर 23,431.50 अंक पर बंद**

मुंबई, 9 सितम्बर (एजेंसियां)। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल में तेजी से घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को बिकवाली देखी गई, विशेषकर आईटी सेक्टर में ज्यादा गिरावट रही। प्रमुख सूचकांकों में यह लगातार तीसरी गिरावट है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 361 अंक गिरकर 75,216 अंक पर खुला और पूरे दिन लाल निशान में रहा। अंतिम घंटे में बाजार में बिकवाली तेज हो गई। सेंसेक्स अंत में 813.35 अंक (1.08 प्रतिशत) नीचे 74,764.23 अंक पर रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 203.60 अंक यानी 0.86 प्रतिशत टूटकर 23,431.50 अंक पर आ गया। यह दोनों प्रमुख सूचकांकों का इस साल 11 जून के बाद का निचला स्तर है। अमेरिकी

शेयर बाजारों में मंगलवार को रही गिरावट का असर आज दुनिया भर में देखा गया। विशेषकर भारतीय बाजारों में आईटी कंपनियों में बड़ी बिकवाली रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में रही तेजी और रुपए में गिरावट से भी निवेश धारणा कमजोर हुई है। लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा आज ढाई प्रतिशत चढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया।

घरेलू स्तर पर सेक्टर आधारित सूचकांकों में निफ्टी आईटी 3.24 प्रतिशत गिर गया। रियल्टी समूह के सूचकांक में 2.23 प्रतिशत और वित्तीय समूह में 1.24 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। धातु समूह की 1.79 प्रतिशत की तेजी को छोड़कर अन्य सभी सूचकांक लाल निशान में रहे। एफएमसीजी, बैंकिंग और मीडिया सूचकांक भी एक प्रतिशत के करीब टूटे।

एनएसई में जिन 3,676 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 2,092 के शेयर नीचे और 1,481 के बढ़त के साथ बंद हुए। अन्य 103 कंपनियों के शेयर अंततः अपरिवर्तित रहे।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 24 के शेयर नुकसान में बंद हुए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर 4.55 प्रतिशत गिर गया। सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली अगली तीन कंपनियां भी आईटी सेक्टर से ही रहीं। इंफोसिस का शेयर 4.43 प्रतिशत, टेक महिंद्रा का 3.87 टीसीएस का 2.26 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक में 2.23 प्रतिशत, हिंदुस्तान यूनीलिवर में 1.89, बजाज फाइनेंस में 1.42, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.39, भारती एयरटेल में 1.14, बीईएल में 1.05, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.03, आईटीसी में 0.91 और इंडिगो में 0.90 प्रतिशत की गिरावट रही।

आधार प्रमाणीकरण क्षमता बढ़ाने की तैयारी में यूआईडीएआई

मुंबई, 9 सितम्बर (एजेंसियां)।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए अपने तकनीकी ढांचे को बड़े स्तर पर मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। यूआईडीएआई के चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा ने बुधवार को कहा कि वर्तमान में आधार प्रणाली प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) संभाल रही है और इसे बढ़ाकर 25 से 30 करोड़ प्रमाणीकरण प्रतिदिन तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई में आयोजित ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026’ में बोलते हुए मिश्रा ने कहा कि आधार के उपयोग की रफ्तार उम्मीदों से कहीं अधिक तेज रही है। उन्होंने कहा, ‘आधार प्रमाणीकरण जिस गति से बढ़ रहा है, उसे देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हूं। अभी हम प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ प्रमाणीकरण कर रहे हैं

■ **प्रतिदिन 30 करोड़ सत्यापन संभालने की तैयारी**

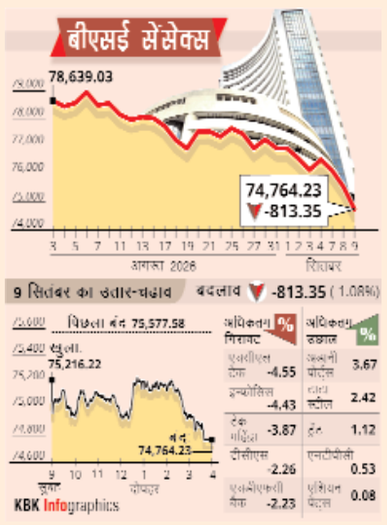

और अब 25 से 30 करोड़ प्रतिदिन की क्षमता के लिए तैयारी कर रहे हैं। ‘उन्होंने बताया कि आधार का उपयोग करने वाली संस्थाओं की संख्या अब 600 से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आधार की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी सुविधा, विश्वसनीयता और कम लागत पर दूरस्थ पहचान सत्यापन की क्षमता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की दक्षता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग आवश्यक होता है और सहयोग के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आधार ने कम लागत पर और दूरस्थ स्थानों के बीच भी भरोसे की व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नीलकंठ मिश्रा ने बताया कि यूआईडीएआई अब कागजी प्रक्रियाओं को कम करके डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रहा है।

सार संक्षेप

जियो पेमेंट सॉल्यूशंस ने शुरू की सीमा पार भुगतान सेवा

मुंबई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इकाई जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (जेपीएसएल) ने बुधवार को सीमा पार भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इससे विदेशों में सामान बेचने वाले कारोबारियों को लाभ होगा। वे दुनिया भर के ग्राहकों से वर्चुअल अकाउंट, इंटरनेशनल कार्ड और स्थानीय भुगतान नेटवर्क के जरिए पैसा ले सकेंगे। जेपीएसएल को भारतीय रिजर्व बैंक से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। इसके तहत वह भारत से बाहर पैसा भेजने और विदेश से भारत पैसा भेजने की सेवा दे सकती है। जियो पेमेंट सॉल्यूशंस ने बताया कि उसका मुख्य फोकस फिलहाल विदेश से भारत के लिए भुगतान आसान बनाने पर है। इस सेवा का फायदा ऑनलाइन विक्रेताओं, डिजिटल कारोबार, फ्री-लांसर्स, क्रिएटर्स और सॉफ्टवेअर सेवा देने वाली कंपनियों को भी मिल सकता है।

कोफोर्ज के चेयरमैन ने दिया इस्तीफ, गिरा स्टॉक

मुंबई। मिडकैप आईट कंपनी कोफोर्ज के अंतरिक ऑर्डट में कंपनी के बोर्ड मूल्यांकन प्रोसेस को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरमैन ओपी भट्ट ने इस्तीफा दे दिया है। भट्ट के इस्तीफे की खबर के बाद बुधवार को कोफोर्ज के शेयर में बड़ी गिरावट देखी गई। अब तक के कारोबार में शेयर 1S 1780.70 रुपए का इंट्रडे लो बनाया है, जो कि उसकी पिछली क्लोजिंग 1,950 रुपए के करीब 8.71 प्रतिशत कम है। फिलहाल सुबह 10:45 पर शेयर 4.50 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,862 रुपए पर था। रेगुलेटरी फाइलिंग में कोफोर्ज ने बताया कि उसके इंटरनल ऑडिटर ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के इंटरनल ऑडिट प्लान के तहत, बोर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस और उससे बनी बोर्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट (बीईआर) की समीक्षा की। यह प्रोसेस भट्ट की देखरेख में किया गया था।

15 क्रिप्टो प्लेटफॉम्र्स को एफआईयू ने जारी किए नोटिस

नई दिल्ली। भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के गैर-अनुपालन के लिए 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी किए हैं। यह जानकारी बुधवार को जारी बयान में दी गई। वित्त मंत्रालय के अनुसार, एफआईयू-इंडिया के डायरेक्टर ने उन संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के तहत ये नोटिस जारी किए हैं, जो जरूरी शर्तों को पूरा किए बिना काम कर रही थीं। इन संस्थाओं में वीक्स, ब्लोफिन, रेजोरेक्स, बिटयूनिक्स , डिजीफाइनेंस, टूबीट, एक्सटी.कॉम, लाटोकन, वू एक्स, पायनिक्स, चेंज नाउ, सिंपल स्वैप, फिक्स्डफ्लोट, व्हाइटबीआईटी और गार्डेरियन शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि एफआईयू डायरेक्टर ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत नोडल ऑफिसर के तौर पर नोटिस जारी किए हैं।

चीनी, चावल नरम, दालों व खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (एजेंसियां)। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बुधवार को चीनी का औसत भाव टूट गया। चीनी के साथ चावल में भी नरमी रही। वहीं, गेहूं की कीमत गत दिवस के स्तर पर पड़ी रही जबकि खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव का रुख देखा गया। मीठे के थोक बाजार में चीनी की औसत कीमत 25 रुपए घटकर 5,541 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। वहीं, गुड़ सात रुपए महंगा होकर 5,976 रुपए प्रति क्विंटल बोला गया। खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत 22 पैसे घटकर 60.31 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई।

औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत तीन रुपए टूटकर 4,143 रुपए प्रति क्विंटल पर रही। गेहूं 2,859 रुपए प्रति क्विंटल के गत दिवस के स्तर पर लगभग स्थिर रहा। आटे में भी टिकाव देखा गया। मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में नवंबर का पाम ऑयल वायदा नौ रिंगिट गिरकर 4,967 रिंगिट प्रति टन रह गया। दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.21 प्रतिशत फिसलकर 70.55 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजार में आज सरसों तेल की औसत कीमत 18 रुपए और सोया तेल की 12 रुपए प्रति क्विंटल टूट गई। वनस्पति का भाव 51 रुपए और मूंगफली तेल का 28 रुपए बढ़ गया। पाम ऑयल 24 रुपए और सूरजमुखी तेल तीन रुपए महंगा हुआ। **दाल-दलहन :** दाल चना 8,010.60 रुपए, मसूर काली 8208.95 रुपए, मूंग दाल 10201.06 रुपए, उड़द दाल 11316.49 रुपए, तुअर दाल 11471.39 रुपए प्रति क्विंटल रही। **अनाज :** (भाव प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2859.83 रुपए और चावल 4142.86 रुपए प्रति क्विंटल और आटा (गेहूं) 3328.15 रुपए प्रति क्विंटल रहा।

‘विकसित भारत’ के लक्ष्य में सीएसआर की अहम भूमिका : जयंत चौधरी

नई दिल्ली, 9 सितम्बर (एजेंसियां)। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने बुधवार को कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसमें जनभागीदारी, सामाजिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार की अधिकांश योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब समाज, उद्योग और नागरिक मिलकर उनमें योगदान दें।

केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि ‘पीपुल फॉर एक्शन’ के तत्वावधान में आयोजित यह पहल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से जुड़े संगठनों, दानदाताओं और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाकर सार्थक संवाद का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सरकार भी

■ **आकांक्षी जिलों तक पहुंचे उद्योगों का सामाजिक निवेश**

कई ऐसी योजनाएं चला रही है, जिनमें नागरिकों, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा कि पीएम सेतु योजना इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।

उन्होंने मीडिया को बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) देश में कौशल विकास का प्रमुख आधार हैं और उद्योग जगत की भागीदारी से इन संस्थानों के पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार क्षमता को और मजबूत बनाया जा सकता है। योजना के तहत सीएसआर फंड के माध्यम से उद्योगों को कौशल विकास के क्षेत्र में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि शिक्षा क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी बेहद जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय ने ‘विद्यांजलि पोर्टल’ इसी उद्देश्य से विकसित किया है, ताकि कंपनियां, संस्थाएं और पूर्व छात्र अपने स्कूलों के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और स्कूल मिलकर विभिन्न परियोजनाएं तैयार करते हैं, जिनमें सीएसआर और सामाजिक योगदान के माध्यम से संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

सार-समाचार

राज्यपाल से मनोनीत मुख्य न्यायाधीश कोगजे ने की सौजन्य भेंट

भोपाल, देशबन्धु। राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे ने बुधवार को लोकभवन में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल श्री पटेल का उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री कोगजे की पत्नी अर्चना अल्पेश कोगजे उनके साथ थीं। इससे पूर्व लोकभवन आगमन पर मनोनीत मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे का अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे।

संदीप ने महिला एवं बाल विकास आयुक्त का कार्यभार संभाला

भोपाल, देशबन्धु। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संदीप जी.आर. ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया। राज्य शासन द्वारा उन्हें इस विभाग के अपर सचिव तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का दायित्व भी सौंपा गया है। संदीप वर्ष 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे छतरपुर एवं सागर जिले के कलेक्टर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। सागर कलेक्टर के रूप में उन्होंने प्रशासन में तकनीक के प्रभावी उपयोग, जनभागीदारी और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए कई अभिनव पहल कीं।

प्रधान आरक्षक भर्ती प्रायोगिक परीक्षा 27 को

भोपाल, देशबन्धु। मध्यप्रदेश पुलिस में प्रधान आरक्षक कम्प्यूटर एवं सहायक उप निरीक्षक कम्प्यूटर भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 27 सितम्बर 2026 को मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र एवं परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं।

विजयादशमी से शुरू होगी दिग्विजय की स्वाभिमान यात्रा

भोपाल, देशबन्धु। दिग्विजय सिंह ने धर्म और आस्था के नाम पर कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 'सनातन स्वाभिमान यात्रा' की घोषणा की है। यात्रा 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर उज्जैन से अयोध्या तक निकलेगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, सत्य, श्रद्धा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाना है।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि यह यात्रा धर्म के नाम पर लूट और श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ के खिलाफ है। उन्होंने विजयादशमी के दिन उज्जैन से अयोध्या तक इसे निकालने का निर्णय लिया है।

दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के नाम पर पारदर्शिता, सत्य और श्रद्धा की रक्षा करना है। साथ ही सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य है।

दुबई के निवेशकों को भाया मध्य प्रदेश : 53 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैश्विक उद्योग जगत को दिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 का न्योता

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छह से आठ सितंबर तक के दुबई दौरे में प्रदेश को 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। एआईएम कांग्रेस-2026 के मंच से मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता और नई औद्योगिक नीतियों को दुनिया के सामने रखते हुए निवेशकों को प्रदेश आने का न्योता दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश का लक्ष्य केवल पूंजी आकर्षित करना नहीं, बल्कि निवेश के साथ तकनीक, बाजार, निर्यात और रोजगार को जोड़ना है। उन्होंने प्रदेश को वैश्विक कंपनियों के लिए दीर्घकालिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया। डीपी वर्ल्ड, शराफ ग्रुप, जेम्स एजुकेशन, राणा होल्डिंग्स, क्रिसेंट एंटरप्राइजेज, चोइथराम्स, वीएफएस ग्लोबल और बी-आह सहित कई वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ निवेश की संभावनाओं पर सीधे संवाद हुआ।

लॉजिस्टिक्स और तकनीक पर खास जोर

डीपी वर्ल्ड के साथ पवारखेड़ा में बहुआयामी लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। शराफ ग्रुप ने रेल-साइडिंग आधारित लॉजिस्टिक्स पार्क

में 30 से 50 मिलियन डॉलर निवेश की संभावना जताई। जेम्स एजुकेशन ने प्रदेश के प्रमुख शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में रुचि दिखाई।

राणा होल्डिंग्स के साथ स्मार्ट विनिर्माण, डेटा सेंटर, हरित हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ई-मोबिलिटी और कृषि मशीनरी पर चर्चा हुई। क्रिसेंट एंटरप्राइजेज ने ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और शहरी अधोसंरचना में निवेश की संभावनाएं तलाशने की इच्छा जताई। चोइथराम्स समूह के साथ आधुनिक खुदरा बाजार, खाद्य प्रसंस्करण और किसानों से सीधे खरीद को बढ़ावा देने पर विचार हुआ।

यूएई से पर्यटन और विमानन सहयोग

यूएई ने मध्य प्रदेश में होटल और आतिथ्य क्षेत्र की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई। मध्य प्रदेश और यूएई के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने पर भी सहयोग की दिशा में पहल हुई। विश्व बैंक के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शासन परियोजनाओं में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

शारजाह स्थित बी-आह के साथ कचरा प्रबंधन, कचरे से ऊर्जा और चक्रीय अर्थव्यवस्था में साझेदारी की संभावनाएं तलाशते हुए इंदौर के स्वच्छता और बायो-सीएनजी मॉडल को वैश्विक तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया गया।

समिट के लिए जुटाया समर्थन

दुबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने यूएई, तातारस्तान, इथियोपिया, अरब देशों और वैश्विक उद्योग जगत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में भागीदारी का निमंत्रण दिया। शारजाह चैंबर के साथ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और निर्यातकों को खाड़ी बाजार से जोड़ने की पहल भी की गई।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में पारदर्शी नीतियों, एकल खिड़की व्यवस्था और समयबद्ध सहयोग के माध्यम से निवेश को गति दी जा रही है।

दुबई दौरे में निवेश के बड़े प्रस्ताव

डीपी वर्ल्ड : पवारखेड़ा में बहुआयामी लॉजिस्टिक्स केंद्र, भंडारण और शीत-श्रृंखला विकसित करने की संभावनाएं।

शराफ ग्रुप : रेल-साइडिंग आधारित लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 30-50 मिलियन डॉलर निवेश की संभावना। करीब 300-600 रोजगार के अवसर।

जेम्स एजुकेशन : प्रमुख एवं उभरते शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में रुचि।

राणा होल्डिंग्स : स्मार्ट विनिर्माण, डेटा सेंटर, हरित हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ई-मोबिलिटी और कृषि मशीनरी में निवेश की संभावनाएं।

क्रिसेंट एंटरप्राइजेज : ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, सूचना प्रौद्योगिकी और शहरी अधोसंरचना में दीर्घकालीन निवेश पर चर्चा।

चोइथराम्स समूह : आधुनिक खुदरा बाजार, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और किसानों से सीधे खरीद की संभावनाएं।

बी-आह : ठोस कचरा प्रबंधन, कचरे से ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था और हरित गतिशीलता में तकनीकी साझेदारी।

विश्व बैंक : कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शासन परियोजनाओं में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की संभावनाएं।

यूएई : पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशने प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश आएगा। विमानन संपर्क बढ़ाने पर भी पहल।

तातारस्तान : उन्नत विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, कृषि और लॉजिस्टिक्स में साझेदारी पर चर्चा।

वैश्विक बाजार में मध्य प्रदेश के उत्पाद : दुबई में चंदेरी, महेश्वरी, बैतूल बेल मेटल, उज्जैन बाटिक, भोपाल जरी-जरदोजी और ग्वालियर कालीन जैसे एक जिला-एक उत्पाद एवं भौगोलिक संकेतक उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग की गई।

लॉजिस्टिक्स, एआई, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन बने आकर्षण के केंद्र

उप मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद चिकित्सा छात्रों का आंदोलन खत्म

स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि होगी

बल प्रयोग पर 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चिकित्सा छात्रों के स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गांधी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि छात्रों की इस मांग पर पहले से ही चर्चा चल रही थी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस विषय पर सतत संवाद कर रहे थे।

प्रतिनिधिमंडल ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त हुए आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की और काम पर लौट आए। शुक्ल ने आंदोलन के पहले दिन छात्रों के साथ पुलिस द्वारा बल प्रयोग के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने युवा चिकित्सकों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा भाव और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने से चिकित्सकों को वास्तविक परिस्थितियों को समझने और व्यापक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने वाले छात्रों के साथ इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कैंपस में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्र-छात्राओं पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। घटना में घायल छात्रों के समुचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

समन्वय से निकला समाधान

प्रशिक्षु, जूडा एवं एमटीए सहित विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय और संवाद स्थापित करने में विद्यार्थी परिषद, डॉ. हितेश वाजपेयी एवं एमटीए अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी पक्षों के बीच सकारात्मक संवाद और आपसी सहमति से पूरे प्रकरण का सौहार्दपूर्ण समाधान निकला। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सभी प्रतिनिधियों को सकारात्मक पहल के लिए बधाई दी। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल का आभार व्यक्त किया।

इंदौर में अतिक्रमण हटाने की दौरान हंगामा

इंदौर, देशबन्धु। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के साउथ टोड़ा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। कुछ स्थानीय लोगों ने कथित अवैध निर्माणों को तोड़े जाने का विरोध किया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। निगम की कार्रवाई के दौरान एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल को एक युवक ने धक्का दे दिया। धक्का लगने से वह जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने हंगामे के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि अतिक्रमण हटाने निगम की टीम पहुंची थी और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। निगम की 100 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम कार्रवाई में जुटी थी। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार सुबह एक बडी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने साउथ तोड़ा क्षेत्र में कान्ह नदी किनारे बने 7 पक्के मकान और 45 कारखाने हटाए। ये सभी शासकीय भूमि पर बने हुए थे। कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस देकर लोगों से अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था, बावजूद इसके जब अवैध निर्माण नहीं हटे तो कार्रवाई करना पड़ी, जबकि लोग कह रहे हैं कि उन्हें सामान हटाने का मौका तक नहीं दिया गया

एडिशनल डीसीपी को धक्का दिया, 6 हिरासत में

रीवा में जच्चा-बच्चा की मौत का मामला

धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया

भोपाल, देशबन्धु। रीवा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव, पिछले दिनों महिला और उसके नवजात की मौत को अपराधिक लापरवाही बताते हुए विधायक अभय मिश्रा ने बुधवार को मंत्रालय के सामने धरना दिया। मिश्रा करीब आधा घंटे ही वहां बैठे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनकी मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफा दें। धरने से पहले मिश्रा ने कहा कि रीवा के सरकारी अस्पताल में एक के बाद एक हो रही मौतों और इससे गुस्साए लोगों की पीड़ा यह दिखाती है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही का संकट है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कल्पना मिश्रा की मौत को कांग्रेस ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी रीवा पहुंचकर धरने में शामिल हो चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। अब सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने राजधानी में मोर्चा खोला तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

उमंग सिंघार ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप

रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को पुलिस द्वारा धरना स्थल से हिरासत में लिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा है। उन्होंने इसे तानाशाही बताते हुए कहा है कि क्या एक जनप्रतिनिधि का न्याय मांगना भी इस सरकार में अपराध हो गया है? उन्होंने कहा कि भाजपा का यह तानाशाही रवैया और दमनचक्र अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी।

जहरीली शराब कांड : दिग्विजय और राजपूत आमने-सामने

भोपाल, देशबन्धु। सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्री गोविंद राजपूत आमने-सामने आ गए हैं। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि जानलेवा शराब बनाने और बेचने वालों को भाजपा नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण था। उन्होंने यह भी कहा कि जहरीली शराब मामले में उनके परिजन भी शामिल हैं।

इससे नाराज मंत्री राजपूत ने वीडियो जारी कर कहा कि विपक्ष राजनीति करने के बजाय सच्चाई सामने लाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के किसी व्यक्ति या परिवार को बदनाम करने वाली भ्रामक जानकारी प्रसारित न की जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि किसी गांव के एक व्यक्ति का संबंध मेरे परिवार से है अथवा वह मेरा रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं पुलिस अधीक्षक सागर से स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री राजपूत द्वारा मंगलवार रात जारी इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने उनके द्वारा दी गई कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद एक बैनर के आधार पर मंत्री राजपूत को घेरा और एक शराब ठेकेदार का नाम उनसे जोड़ दिया।

अधिकारियों को त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

भोपाल, देशबन्धु। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना। सिंह ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जनसमस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विभाग की कार्रवाई आवश्यक है, उन्हें शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश मंत्री राजेन्द्र सिंह राजपूत उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक जनसमस्या का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े विषयों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन की जनसमस्याओं का समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करना, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, 8 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, कहा-

आंगनबाड़ी को समाज से जोड़कर पोषण अभियान को जनआंदोलन बनाएं

बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के में सहयोग के लिए एम्स सहित 4 संस्थाओं से एमओयू

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का बुधवार को इंदौर से राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। 'हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' थीम के साथ 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य को लेकर जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चे ही प्रदेश और देश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को अभिभावकों, सरपंचों, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों तथा सामाजिक और

सांस्कृतिक संस्थाओं से जोड़ा जाए। समाज की सक्रिय भागीदारी से आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए प्रयोग करने तथा सफल नवाचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करने का भी आह्वान किया, जिससे दूसरे केंद्र भी उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि पोषण माह के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। गर्भवती और धात्री माताओं को पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और बच्चों की देखभाल के प्रति जागरूक करने के साथ कुपोषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान रहेगा। मंत्री ने बताया कि विभाग ने आंगनबाड़ी भवनों की उपलब्धता बढ़ाने, मिनी आंगनबाड़ियों को मुख्य आंगनबाड़ी में उन्नयन करने और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं।

स्थानीय अनाज और पारंपरिक व्यंजनों पर जोर

पोषण माह के शुभारंभ पर लता मंगेशकर सभागृह परिसर में पोषण मेला और रेसिपी प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। यहां टेक होम राशन, गर्म पका भोजन, स्थानीय दालों, चना, मूंगफली, सोया, दूध एवं दुग्ध उत्पादों, मिलेट्स और मौसमी सब्जियों से तैयार पौष्टिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। 'नो योर प्रोटीन-अपने प्रोटीन को पहचानें' अभियान के जरिए परिवारों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रोटीन के स्रोतों और संतुलित आहार के महत्व की जानकारी दी गई।

पोषण माह के शुभारंभ अवसर पर बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन भी किए गए। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, एम्स, आईपीई ग्लोबल और नई दिशा फाउंडेशन के साथ हुए एमओयू के माध्यम से बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

राज्यसभा सांसद डॉ. कविता पाटीदार ने कहा कि 'हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' के संदेश के साथ बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने पोषण ट्रैकर, वन स्टॉप सेंटर और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

सोने के 5 बिस्कुट बरामद, एक गिरफ्तार

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कूचबिहार जिले के दिनहाटा पुलिस स्टेशन के तहत साहिबगंज इलाके में गाड़ियों की रूटीन चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया और 600 ग्राम से ज्यादा वजन के सोने के पांच बिस्कुट जब्त किए, जिनकी कीमत 90 लाख रुपए से ज्यादा है। सीमा पार तस्करी के बारे में मिली खास जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम ने मंगलवार रात साहिबगंज रोड पर चेकिंग बढ़ा दी।

पत्रकार प्रकाशन प्रा.लि. के लिए गिरिराज चाचा द्वारा श्री सिद्धि विनायक प्रिंटर्स, प्लाट नं. 26 बी देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. 462011 से मुद्रित एवं प्रकाशित, संपादक: पलाश सुरजन, कार्यकारी संपादक: ज़ाकिर अली* फोन 0755-4222971, ई-मेल deshbandhubpl1@yahoo.co.in प्रेस पंजीयन-प.स. 45096/85 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।